

[2017] 13 एस. सी. आर. 48

बीरबल चौधरी उर्फ मुखिया जी

बनाम्

बिहार राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 701/2012)

06 अक्टूबर, 2017

(ए. के. सिकरी और आर. के. अग्रवाल, न्यायमूर्तिगण)

दंड संहिता, 1860:

धाराएँ 364 ए/34,395 और 412- अभियोजन-के तहत-अपीलकर्तओं को अभियुक्त निचली अदालत द्वारा गवाहों की गवाही, टीआई (टेस्ट आइडेंटिफिकेशन) परेड और अभियुक्तों से बरामदगी के आधार पर दोषसिद्धि-दो अपीलार्थी-अभियुक्तों को उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि को देखते हुए मौत की सजा सुनाई गई और शेष अपीलार्थी-अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई-उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि की पुष्टि की-हालांकि मृत्युदंड के साथ-साथ आजीवन कारावास की सजा को घटाकर 20 साल कि कठोर कारावास में बदल दिया गया-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया: अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थियों-अभियुक्त-के खिलाफ अपने मामले को विधिवत साबित कर दिया है और सजा को उचित ठहराया है।

धाराएँ 364 ए और 368- के तहत अपराध-अभिनिर्धारित किया गया-धारा 368 उसमें विहित अपराध को धारा 364 ए के बराबर रखती है। कानूनी कल्पना के आधार पर एक वैधानिक धारणा को उठाकर कि पूर्व को उत्तरार्द्ध के तहत एक अपराध माना जाता है। अगर सबूत है।

सजा/सजा:

आजीवन कारावास-आजीवन कारावास का अर्थ है पूर्ण आजीवन कारावास और न कि 14 साल की सजा ।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:

धारा 401-सजा बढ़ाने से पहले- नोटिस का अभिनिर्धारण आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास में बदलने के लिए धारा 401- के तहत नोटिस की आवश्यकता नहीं है। आजीवन कारावास को 20 साल के कारावास में बदलना वास्तव में सजा में कमी है न कि वृद्धि क्योंकि आजीवन कारावास का अर्थ है पूर्ण जीवन के लिए सजा।

धारा 464-आरोप तय करने में चूक का प्रभाव, आरोप में अनियमितता या आरोपों का गलत प्रत्युत्तर अभिनिर्धारित:- सक्षम अधिकारिता को इस आधार पर अमान्य माना जाएगा कि कोई आरोप नहीं गठित गया था या आरोप में कोई अनियमितता या आरोपों का गलत प्रत्युत्तर नहीं दिया गया था, जब तक कि अदालत इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती कि न्याय की विफलता इसके कारण हुई थी। ऐसी स्थिति में अदालत द्वारा कोई सजा नहीं दी जाएगी ।

अपील को खारिज करते हुए अदालत ने कहा:

1.1 पीड़ितों के अपहरण और कारावास में ए-13 की भागीदारी पूरी तरह से संलिप्त है। उसके खिलाफ साक्ष्य यह है कि पीड़ितों ने पाया कि ए-13 को अन्य लोगों द्वारा मुखिया जी के रूप में उल्लिखित किया गया था। दूसरा प्रमाण जो पी० डब्लू-17 ने प्रस्तुत किया कि यह वही व्यक्ति है जो अपहृतों को अपने घर में कुछ दिनों के लिए रखा था। हालांकि पीडब्लू-17 ने शिनाख्त परेड में भाग नहीं लिया, लेकिन न्यायालय में, उन्होंने एक स्पष्ट बयान दिया कि हालांकि अन्य आरोपी व्यक्ति अदालत में मौजूद थे, लेकिन उन्हें न्यायालय में ए-13 नहीं मिला। इससे पता चलता है कि पीडब्लू-17 उसकी पहचान कर सकता था और जब उसने पाया कि वह उस दिन अदालत में मौजूद नहीं था, तो उसने विशेष रूप से इस आशय का उल्लेख किया। पीडब्लू-17 ने अदालत

में फिर से पेश होने पर ए-13 की विधिवत पहचान की और उल्लेख किया कि पीडितों को ए-13 के घर में रखा गया था जो गंज भरसरा के मुखिया थे। इस पर ध्यान देते हुए, उच्च न्यायालय ने स्पष्ट टिप्पणी की है कि ए-13 ने न तो उक्त पहचान पर विवाद किया है और न ही इस पहलू पर प्रतिपरीक्षण में कोई सवाल उठाया है। पीडब्लू-18 ने शिनाख्त परेड में ए-13 की पहचान की थी, लेकिन अदालत में उसने उसकी पहचान नहीं की। न्यायालय में ए-13 को पहचान करने से इनकार करने वाले पीडब्लू-18 के आचरण को अधिक विश्वास नहीं दिया जा सकता है। इस आशय से पीडब्लू-18 पक्षद्रोही साबित हुआ। शिनाख्त परेड के दौरान, उन्होंने ए-13 की पहचान की थी और यह टी. आई. पी. शिनाख्त परेड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (पी. डब्ल्यू-9) की उपस्थिति में आयोजित किया गया था, जिन्होंने उपरोक्त प्रभाव के लिए स्पष्ट रूप से गवाही दी थी। इसके अलावा, पीडब्लू-17 (जिसे नीचे दोनों अदालतों द्वारा भरोसेमंद माना जाता है) के द्वारा दिए गए बयान की पर्याप्त सबूत के रूप में पेश किया गया कि उसे ए-13 के घर में रखा गया था। (पैरा 26-29) (67-एफ-एच; 68-ए-बी, ई; 70-ए)

1.2 जहां तक फिरौती की मांग का सवाल है, पहले ही दिन जब मुखबिर ने अपनी लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी, तो उसने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि वह आश्वस्त था कि अपहरण फिरौती के लिए किया गया था। एक अन्य पहलू यह है कि अपहृत तीन व्यक्तियों में से चालक (पीडब्लू-18) को अगले ही दिन रिहा कर दिया गया था, जबकि अन्य को 52 दिनों तक कैद में रखा गया था। प्रदर्श सं-8 (पीडब्लू-17 द्वारा कारावास के दरम्यान लिखा गया पत्र को पीडब्लू-20 हस्ताक्षरित) भी पीडब्लू-5 से फिरौती राशि का भुगतान करने और उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए कह गया है। फिरौती की मांग पीडब्लू-5 के बीच बातचीत से स्पष्ट होता है, जब अभियुक्तों में से दो कि पहचान ने एक मोबाइल से कॉल करने पर फोन नंबर से हुई जिससे अपहरणकर्ताओं के साथ संपर्क साध कर फिरौती के लिए 50 लाख रु. में मांग की गई। और आगे कहा कि वे पीडब्लू-17 की अंगूठी और फिरौती का दावा करे के लिए अपने कारावास (केद्र) के प्रमाण में एक पत्र (जिसे प्रदर्श सं.-08 अंकित किया गया है) भी भेजे थे। प्रदर्श-08 में कहा गया है कि पीडब्लू-5 को जल्द से

जल्द उन्हें छुड़ाने की व्यवस्था करनी चाहिए। साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 63 (बी) में दिए गए तरीके से टेलीफोन अधिकारियों से आवश्यक रिपोर्टें द्वारा जांच के दौरान रिकॉर्ड में लाए गए मोबाइल फोरेंसिक साक्ष्य स्पष्ट रूप से साबित करते हैं कि वास्तव में फिरौती की मांग की गई थी। अन्यथा, यह अपीकर्तओ का बचाव (डीफेंस) नहीं है कि पीड़ितों और अपीलकर्ताओं के बीच किसी भी प्रकार की शत्रुता थी। विद्यमान तरीके से कृत अपहरण इस बात के प्रमाण है, कि काफी सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध तरीका से, अलग-अलग भूमिकओ के साथ विशेष लोगो द्वारा किया गया है। इसलिए, स्पष्ट रूप से स्थापित होता है। कि वास्तव में फिरौती की मांग की गई थी। यह कि वास्तव में भुगतान किया गया था या नहीं अप्रासंगिक है। फिरौती की मांग अभियोजन पक्ष द्वारा विधिवत साबित की गई है। [पैरा 30,31 और 35] [70-बी-सी, ई-एच; 71-ए-बी; 72-ए]

मल्लेशी बनाम कर्नाटक राज्य (2004) 8 एस. सी. सी. 95: (सर्वोच्च न्यायालय मामला) [2004] 4 पूरक एस. सी. आर. 441-(सर्वोच्च न्यायालय रिकार्ड) पर आधारित।

1.3 अपीलार्थी के हित में आरोप-पत्र के समेकन के बाद अभियोजन पक्ष का गवाह सं.-1 से अभियोजन पक्ष का गवाह सं.-6 की प्रतिपरीक्षण ली गई। पहला आरोप पत्र में जब अभियोजन पक्ष के गवाह सं.-01 से अभियोजन पक्ष के गवाह सं.06 के परीक्षण किया गया था तो उस आरोप पत्र में अपीलार्थी का नाम नहीं था। इससे स्पष्ट होता है, कि अपीलार्थी उपस्थित नहीं था। यही कारण है कि इनगवाहों से फिर से पूछताछ की गई और अपीलार्थी को उनसे जिरह करने का पूरा अवसर दिया गया। अपीलार्थी के लिए इन गवाहों के बयान का उल्लेख करने से कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं होता है जब पहली बार में उनकी जांच की गई है क्योंकि दोनों अवसरों पर उनकी गवाही समान रही है। [पैरा 37] [72-जी; 73-ए]

1.4 निचली अदालत ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 364 ए/34 के तहत दोषसिद्धि के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। आजीवन कारावास का अर्थ पूर्ण जीवन होगा न कि 14 वर्ष की सजा जो कि अत्यधिक

असमान या अपर्याप्त हो सकती है और जिसे आजीवन कारावास नहीं कहा जा सकता है। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी ए-13 की सजा को संशोधित करते हुए, वास्तव में, उसे आजीवन कारावास से घटाकर 20 वर्ष कर दिया। इसलिए, धारा 401 Cr.P.C के तहत कोई नोटिस देने का सवाल ही नहीं उठा। [पैरा 36] [72-बी-डी]

स्वामी श्रद्धानंद (2) @मुरली मनोहर मिश्रा बनाम कर्नाटक राज्य
(2008) 13 एस. सी. सी. 767:[2008] 11 एस. सी. आर.
93-पर आधारित

विकास यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2016) 9
एससीसी 541:[2016] 8 एस. सी. आर. 872-विख्यात मामला

मुथुरामलिंगम और एवम अन्य बनाम राज्य द्वारा-पुलिस निरीक्षक
(2016) 8 एस. सी. सी. 313 [2016] 5 एस.सी.आर 30 पर
अनुसरण किया गया।

2. ए-6 को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 395 के तहत भी दोषी ठहराया गया है। पीडब्लू-17 ने टीआईपी में विशेष रूप से ए-6 की पहचान की है। उच्च न्यायालय ने इस टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड को दोषरहित माना है। आई. पी. सी. की धारा 395 डकैती के लिए सजा से संबंधित है। इस प्रावधान को लागू किया गया था क्योंकि पांच से अधिक संख्या में अपहरणकर्ताओं ने अपहर्तों से उनके कब्जे में रखे धन को लूट लिया था। यह स्वयं पीडब्लू-17, 18 और 20 के अपहरण की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त है। यह भी महत्वपूर्ण है कि पीडब्लू-19, जो इस मामले में जांच अधिकारी (आईओ) थे, ने जिस तरह से जांच की, उसका विस्तार से वर्णन किया है, जिससे पता चलता है कि जांच के दौरान आरोपी व्यक्तियों के नाम सामने आते रहे और उसी के अनुसार जांच आगे बढ़ती रही। जहाँ तक पीडब्लू-18 के बयान का संबंध है, वह अपनी सुरक्षा के डर से मुकर (पक्षद्रोही) हो गया था। हालाँकि पीडब्लू-18 ने धारा 161 Cr.P.C के तहत जो बयान दर्ज किया गया था, उसके विपरीत गवाही दी थी, अदालत में उसके बयान के तीन दिनों के भीतर, जब

उसे उसकी सुरक्षा का आश्वासन दिया गया तब उसने एक नया आवेदन दायर किया और आरोपी व्यक्तियों की पहचान की। [पैरा 39,40 और 41] [73-सी, ई; 74-डी-एफ]

सुमन सूद @कवालजीत कौर बनाम राजस्थान राज्य ऑल इण्डिया रिपोर्टर 2007 एससी 2774:[2007] 6 एस. सी. आर. 499; महाबीर बनाम दिल्ली राज्य ए. आई. आर. 2008 एस. सी. 2343: (2008) 6 एस. सी. आर. 361-पर निर्भर था।

मोटिलाल/यादव बनाम बिहार राज्य (2015) 2 एस. सी. सी. 647; रॉनी उर्फ रोनाल्ड जेम्स अलवारिस एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य (1998) 3 एस. सी. सी. 625:(1998) 2 एससीआर 162; सुरेश चंद्र बहरी और अन्य बनाम बिहार राज्य-बिहार राज्य (1995) 1 पूरक एस.सी.सी. 80:[1994] पूरक।एस. सी. आर. 483-से संदर्भित।

3. जबाब दायर की गई थी (पक्ष लिया गया था कि) कि ए-14, ए-10, ए-11 और ए-12 का नाम पीडब्लू-17 या पीडब्लू-18 या पीडब्लू-20 द्वारा नहीं लिया गया था और ना ही उनके मामलों में, कोई टेस्ट आइडेटीफिकेशन परेड की गई थी और अदालत में भी गवाहों द्वारा उनकी पहचान नहीं की गई थी। उनके खिलाफ एकमात्र आरोप यह था कि उन्होंने गिरफ्तारी के समय पीड़िता को खाना खिलाया था।इन व्यक्तियों को आई. पी. सी. की धारा 34 की तहत दोषी ठहराया गया है। यह तर्क देने की मांग की गई कि तत्काल मामले में धारा 34 की सहायता गलत तरीके से ली गई थी। यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा कि क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 34 या धारा 149 या दोनों प्रावधान आकर्षित हैं। धारा 149 की गैर-प्रयोज्यता आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत अभियुक्त व्यक्तियों को दोषी ठहराने में कोई बाधा नहीं है, यदि साक्ष्य उन सभी के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में अपराध करने का खुलासा करता है। निचली अदालतों ने सही निष्कर्ष निकाला है कि सभी दोषी व्यक्तियों द्वारा फिरौती के लिए अपहरण के अपराध को करने का एक समान इरादा था। ए-14 के अनुसार, यह भी प्रस्तुत किया गया था कि पीडब्लू-

17 ने किसी विशेष घर की पहचान नहीं की थी। हालाँकि, यह रिकॉर्ड में आया है कि अभियुक्तों में से एक ने अपने इकबालिया बयान में कहा था कि पीड़ितों को उनके घर में रखा गया था, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा इस कारण से मान्यता दी गई है कि इसकी पुष्टि पीडब्लू-17 के साक्ष्य से होती है जिसने ए-14 के घर की पहचान की थी। इसलिए, यह तर्क कि किसी विशेष घर की पहचान नहीं की गई थी, सही नहीं है। [पैरा 45,46,47,49 और 50] (76-एफ-जी; 77-ए; 78-ए; 80-ए-डी)

मोहन सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य ए. आई. आर 1963 एस. सी. 174:[1962] पूरक एससीआर 848; चित्तरमल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य (2003) 2 एससीसी 266:[2003] 1 एस. सी. आर. 49-से संदर्भित।

4. ए-9 के खिलाफ आरोप है कि वह उस टीम दल का हिस्सा था जिसने पीड़ितों का अपहरण किया था। शिनाख्त परेड के साथ-साथ अदालत में भी उनकी पहचान की गई थी। उनका एकमात्र तर्क था कि आई. पी. सी. की धारा 364 ए के तहत दोषी ठहराने का कोई कारण नहीं था और उनकी दोषसिद्धि आई. पी. सी. की धारा 364 के तहत होनी चाहिए थी क्योंकि अपहरण के बाद, उन्हें कोई भूमिका नहीं सौंपी गई है और इसलिए, फिरौती के आरोपों को उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। एक बार तीन व्यक्तियों के अपहरण में ए-9 की भूमिका बिना किसी संदेह के स्थापित हो जाती है और यह भी स्थापित हो जाता है कि अपहरण फिरौती के लिए किया गया था, जो वास्तव में मांग की गई थी, और उपरोक्त कृत्यों के पीछे एक सामान्य इरादा था, ए-9 को आईपीसी की धारा 364 ए के तहत सही तरीके से दोषी ठहराया गया है। [पैरा 52 और 53] [80-एफ-जी]

5. ए-1 उन लोगों में से एक है जो पीडब्लू-17,18 और 20 का अपहरण करने वाली टीम का हिस्सा था। उच्च न्यायालय ने ठीक ही कहा कि अपहरण और कारावास में अपीलार्थी की पहचान और संलिप्तता स्पष्ट रूप से साबित होती है। टी. आई. पी. में पहचानी गई जाँच के दौरान दी गई जानकारी पर पुलिस द्वारा वस्तुओं की

बरामदगी सबूत थी। जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत स्वीकार्य। [पैरा 54]
[81-ए; 83-ए]

6.1 ए-8 को आई. पी. सी. की धारा 364 ए/34 के तहत दोषी ठहराया गया है और आई. पी. सी. की धारा 412 के तहत आरोप से बरी कर दिया गया है। इस दलील के संबंध में कि आरोप पत्र में उनके नाम का उल्लेख नहीं किया गया था, इनवेस्टिंग ऑफिसर (पी. डब्ल्यू.-19) ने विस्तार से बताया है कि जाँच, के दौरान इन अभियुक्त व्यक्तियों के नाम सामने आते रहे और तदनुसार जाँच आगे बढ़ाई गई है। यही कारण है कि ए-8 सहित अन्य व्यक्तियों को शामिल करते हुए दूसरा आरोप पत्र दायर किया गया था। उच्च न्यायालय में इस तरह की याचिका नहीं दी गई थी। जहाँ तक उसके खिलाफ धारा 364 ए के तहत आरोप की अनुपस्थिति का संबंध है, हो सकता है कि इससे चीजें बेहतर न हों। अपीलार्थी इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उस पर विशेष रूप से आई. पी. सी. की धारा 368 के तहत आरोप लगाया गया था। यह प्रावधान यह स्पष्ट करता है कि एक जो व्यक्ति यह जानते हुए कि यह अपहृत है, उसे गलत तरीके से छुपाता या बंद करता है, वह उन्ही नतीजों का भागिदार होता है जो व्यक्ति (अपहरकर्ता) जिस इरादे या उद्देश्य के साथ अपहृत का अपहरण करता है। आरोपों के बयान में सी.आर.पी.सी. (दंड प्रक्रिया संहिता) की धारा 313 के तहत यह स्पष्ट रूप से उनके समक्ष रखा गया था, कि उसके खिलाफ आरोप था कि उसने अपहृत व्यक्तियों को यह जानते हुए कैद में रखा था कि उनका अपहरण कर लिया गया है। इस प्रकार, ए-8 के खिलाफ अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित विशिष्ट मामला यह था कि उसने पीड़ितों को इस जानकारी के साथ कारावास में रखा था कि उनका अपहरण कर लिया गया था। इस प्रकार, उसके खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 368 में निर्धारित घटक स्थापित होता है। एक बार यह साबित हो गया है, कि आई. पी. सी. की धारा 364 ए के परिणाम, जिसके लिए अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों को दोषी पाया गया था, लागू होंगे। आई. पी. सी. की धारा 368 में इसमें निर्धारित अपराध को धारा 364 ए के बराबर रखा गया है, जिसमें कानूनी कल्पना के आधार पर एक वैधानिक अनुमान लगाया गया है कि यदि

सबूत हैं तो पूर्व को उत्तरार्द्ध के तहत एक अपराध माना जाता है। [पैरा 56,57,58 और 59] (83-सी-ई, जी-एच; 84-ए-बी)

सुमन सूद @कवालजीत कौर बनाम राजस्थान राज्य एआईआर 2007 एससी 2774:[2007] 6 एस. सी. आर. 499-पर निर्भर।

6.2 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 464 में यह प्रावधान है कि सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा किसी भी सजा को इस आधार पर अमान्य नहीं माना जाएगा कि कोई आरोप नहीं गठित किया गया था या आरोप में कोई अनियमितता या आरोपों का गलत जवाब नहीं दिया गया था, जब तक कि न्यायालय इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता कि न्याय की विफलता इसके कारण हुई थी। वर्तमान मामले में, ए-8 के प्रति ऐसा कोई पूर्वाग्रह नहीं किया गया है जो उसके खिलाफ लगाए गए आरोप के तत्वों को जानता था। [पैरा 60] [(84-ई]

7. आपराधिक अपील संख्या 703-704/2012 में अपीलार्थियों के दोषी ठहराने में निचली अदालतों के फैसलों में कोई त्रुटि नहीं है। [पैरा 62] [84-जी]

वाद विधि संदर्भ

[2016] 8 एस. सी. आर. 872	विशिष्ट पैरा 23
[2004] 4 सप्लीमेंट एस. सी. आर. 441	पैरा 33
[2008] 11 एस. सी. आर. 93	पैरा 36
[2016] 5 एस. सी. आर. 30	पैरा 36
[2007] 6 एस. सी. आर. 499	पैरा 41
[2008] 6 एस. सी. आर. 361	पैरा 42
(2015) 2 धारा 647	पैरा 43

[1998] 2 एस. सी. आर. 162	पैरा 43
[1994] 1 सप्लीमेंट, एस. सी. आर. 483	पैरा 43
[1962] सप्लीमेंट, एस. सी. आर. 848	पैरा 47
[2003] 1 एस. सी. आर. 49	पैरा 48

क्रिमिनल अपीलेट ज्यूरिशन : आपराधिक अपील सं. 701/2012।

2008 के आपराधिक अपील (डी. बी.) संख्या 648 में पटना में उच्च क्षेत्राधिकार के न्यायिक निर्णय और आदेश से

के साथ

2012 की आपराधिक अपील संख्या 702, 705-706, 708, 707 और 703-704

और

2013 की आपराधिक अपील No.1858

आर. बसंत, एस. बी. उपाध्याय, वरिष्ठ अधिवक्ता, अब्बय कुमार, हिमांशु, विनीत कुमार, सिंह, बिलाल खान, संतोष मिश्रा, सुजीत कुमार सिंह, परम कुमार मिश्रा, सुश्री अनीशा उपाध्याय, निशांत कुमार, सुश्री शर्मिला उपाध्याय, अभिजात पी. मेध, नकुल दीवान, सी. जॉर्ज थॉमस, सुश्री तान्या श्री, जैन मकबूल, एजाज़ मकबूल, कुमार राजेश सिंह, सुश्री पूनम सिंह, सुश्री निरंजना सिंह, गौरव अग्रवाल, अभिकल्प प्रताप सिंह, टी. माही पाल, अधिवक्ता अपीलार्थियों के लिए।

रत्नाकर दास, वरिष्ठ अधिवक्ता, अखिलेश कुमार पांडे, गोपाल सिंह, कुमार मिलिंदअभिनव मुखर्जी, सिद्धार्थ गर्ग, सुश्री बिहू शर्मा, सुश्री पूर्णिमा कृष्णा, अधिवक्ता उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय ए. के. सिकरी, न्यायमूर्ति

निर्णय

1) इसमें ग्यारह अपीलार्थी, उन पंद्रह व्यक्तियों में से, जिन्होंने विचारण का सामना किया है, विभिन्न रूप से निम्नलिखित के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराए गए हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 364 ए, 34,395 और 412 के तहत दंडनीय अपराधों को करने के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) का, उच्च न्यायालय द्वारा 30 मार्च, 2010 के सामान्य आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा उनकी दोषसिद्धि की पुष्टि पर सवाल उठाता है, जो अपीलों के एक समूह में दिया गया था। उपरोक्त आरोपों पर अपनी दोषसिद्धि को सुनिश्चित करते हुए, अपीलकर्ता और इसी तरह के अन्य लोगों को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है।

2) सत्र न्यायालय ने उन्हें पूर्वोक्त अपराधों का दोषी पाते हुए दो अपीलकर्ताओं कृष्ण बिहारी सिंह उर्फ कृष्णा सिंह और जवाहर कोयरी उर्फ जवाहर सिंह उर्फ नेता जी को मृत्युदंड दिया था। तथापि, अपील/संदर्भ पर उच्च न्यायालय द्वारा दंडादेश को कम कर दिया गया है और उन्हें 20 वर्ष के कारावास की सजा दी गई है। उच्च न्यायालय ने, यह राय व्यक्त करते हुए कि सभी अपीलार्थियों के कार्य समान इरादे से संचालित किए गए थे, अन्य अपीलार्थियों के आजीवन कारावास की दोषसिद्धि भी 20 वर्ष निर्धारित की गई है।

3) यह मामला अजय शंकर मिश्रा (पीडब्ल्यू-17) के अपहरण से संबंधित है। मनोज सिंह (पीडब्लू-18) और राजू मिश्रा (पीडब्लू-20), जिनके बारे में अभियोजन पक्ष का दावा है, वे लोग फिरौती निकालने के लिए प्रतिबद्ध थे। अरुण कुमार मिश्रा की लिखित रिपोर्ट (मुखबिर पीडब्लू-5 के रूप में मुकदमे के दौरान जांच की गई और बाद में दर्ज एफआईआर से पता चलता है कि पीड़ित पीडब्ल्यू-17 और मुखबिर (पीडब्ल्यू-5) एक साथ व्यवसाय कर रहे थे, जिसमें पीडब्ल्यू-17 मुख्य रूप से अपने व्यावसायिक सहयोगियों से बकाया राशि एकत्र करने के लिए जिम्मेदार था। 20 नवंबर, 2006 को पीडब्लू-17, मुखबिर के चचेरे भाई पीडब्लू-20 और ड्राइवर/चालक

पीडब्लू-18 के साथ, बकाया राशि एकत्र करने के उद्देश्य से, सफेद मारुति जिप्सी नंबर बीआर 1 पी 2619 में बक्सर छोड़ दिया। अपने व्यावसायिक सहयोगियों जैसे संजय जायसवाल (पीडब्ल्यू-1), राजेश कुमार जायसवाल (पीडब्ल्यू-2), संदीप कुमार जायसवाल (पीडब्ल्यू-3), परवेज हसन अंसारी (पीडब्ल्यू-4) और अन्य से कुल 4 लाख रुपये एकत्र करने के बाद वे वापस लौट रहे थे। जबकि उन्होंने दो बार टेलीफोन पर सूचित किया, अंतिम बार शाम 4.30 बजे, वे घर नहीं लौटे और अगले दिन लापता पीड़ितों की तलाश में बिताया। रिकॉर्ड से आगे पता चलता है कि अगले दिन शाम 6 बजे के आसपास, कथित सफेद जिप्सी को एक मोटरसाइकिल और एक चांदी के रंग बोलेरो रामपुर जमुली नहर रोड पर जमुली की ओर जाते हुए देखा गया। इसके अतिरिक्त, यह भी दर्ज किया गया कि उसी दिन अर्थात् 21 नवम्बर, 2006 को लगभग रात 8.45 बजे ड्राइवर पीडब्ल्यू-18 ने सोनबरसा से सूचना देने वाले पीडब्ल्यू-5 से संपर्क किया और उन्हें बताया कि सात अज्ञात व्यक्तियों ने बंदूक की नोक पर पिछली शाम लगभग 5 बजे दो मोटरसाइकिलों के साथ वाहन को ओवरटेक करके पीड़ितों अजय शंकर मिश्रा और राजू मिश्रा का अपहरण कर लिया था और चालक पीडब्ल्यू-18 को अपहरणकर्त्ताओं ने सोनबरसा छोड़ दिया था। प्राथमिकी में यह भी उल्लेख किया गया था कि अपहरणकर्त्ताओं ने फिरौती निकालने के उद्देश्य से उक्त अपराध किया था।

4) जांच के बाद, आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 173 के तहत बक्सर के मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के समक्ष एक आरोप पत्र दायर किया गया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अपीलार्थियों द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 364 ए, 395, 412 और 120 बी के तहत अपराध किए जाने का आरोप लगाया गया। अभियोजनो ने अपने दवा को साबित करने के लिए प्रमाण के रूप में 22 गवाहों को प्रस्तुत किया। मुखबिर पीडब्ल्यू-5 द्वारा दिए गए बयान के अनुसार, ड्राइवर पीडब्ल्यू-18 की रिहाई के अगले दिन, वे पुलिस के साथ घटना और कारावास के स्थान पर गए। पीडब्ल्यू-5 के नौकर रिकू का एक मोबाइल सिम कार्ड संपर्क स्थापित करने के लिए अपहरणकर्त्ताओं को भेजा गया था और जिसके माध्यम से 50 लाख रुपये की मांग की गई थी। पीड़ित जीवित हैं या नहीं, इसका सबूत मांगने पर आरोपी व्यक्तियों ने उन्हें

सूचित किया कि वे पीड़ित की घड़ी और अंगूठी भेज रहे हैं और पीड़ित अजय शंकर मिश्रा को मोबाइल पर बात करने की अनुमति दी। यह भी कहा गया कि आरोपियों ने जवाहर कोइरी और सुरेश कोइरी पीडब्लू 17 और 20 के रूप में अपने नाम का खुलासा किया। पीडब्ल्यू-17 और 20 को 52 दिनों के बाद 11 जनवरी, 2007 को रिहा किया गया था, हालांकि चालक, पीडब्ल्यू-18 को अपहरण के अगले दिन की रिहा कर दिया गया था। यह भी पता चलता है कि पीड़ितों की रिहाई के बाद, पुलिस उन्हें उस स्थान पर ले गई जहां उन्हें पहचान के लिए अपहरण के दौरान रखा गया था और बाद में पुलिस ने उनकी जानकारी के आधार पर एक स्थान मानचित्र तैयार किया।

5) जाँच अदालत ने अपने आदेश के द्वारा सभी अभियुक्तों (अपीलकर्ताओं) को धारा 364A/34, 375 एवं 412 भा.द.वि. के तहत दोषी ठहराया यद्यपि अपीलकर्ताओं को धारा 120 बी.भ.द.वि. के तहत आरोपों से मुक्त कर दिया। न्यायालय ने अपीलार्थियों को अभियोजन, परीक्षण पहचान परेड (टीआईपी) चार्ट के नेतृत्व में 22 गवाहों की गवाही के आधार पर दोषी ठहराया, जिसमें पीड़ितों ने अपीलार्थियों की पहचान की, अभियुक्त कृष्ण सिंह के घर में रखी गई अलमारी से 1,50,000/- रुपये की वसूली की, जिसे कथित अभियुक्त द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी, यह साबित करने में भी विफल रहा कि यह उसके कब्जे में कैसे आया। दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष ने स्पष्ट रूप से साबित कर दिया कि पीड़ितों ने अपने व्यावसायिक सहयोगियों से बकाया राशि प्राप्त की थी, जिसे उनके अपहरण के समय आरोपी व्यक्तियों द्वारा ले लिया गया था, जिसमें से नोटों के दो बंडल एक 'बाबूसाहब' को सौंप दिए गए थे, जिसके पास एक राइफल थी और वह चांदी रंग का बोलेरो चला रहा था। पीड़ित ने बाबूसाहब की पहचान कृष्ण सिंह के रूप में की, जो आरोपी अपीलकर्ता है। इसके अतिरिक्त, फिरौती की मांग मुखबिर (पीडब्लू-5) के साक्ष्य द्वारा, पीड़ित (पीडब्लू-17) को पत्र जब्ती सूची के साथ-साथ टी0 आई0 पी0 चार्ट साबित की गई थी।

6) यद्यपि, चार अभियुक्तों लाल मोहर सिंह, प्रभावती देवी, राजबहादुर सिंह उर्फ चुन्नू सिंह और कृष्णा सिंह पर भारतीय दंड संहिता की धारा 412 के तहत इस अपराध के लिए आरोप लगाया गया था क्योंकि कृष्णा सिंह के घर की अलमारी से

1,50,000/- रुपये की वसूली की गई थी, लेकिन निचली अदालत ने अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन पक्ष इस तथ्य को साबित स्थापित करने में विफल रहा था कि इन चार अभियुक्तों को इस बात की जानकारी थी या विश्वास करने का कारण था कि अलमीरा से बरामद धन लूटा गया था। ऐसी परिस्थिति में, न्यायालय ने आगे अभिनिर्धारित किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा ४१२ के तहत अपराध केवल अपीलार्थी कृष्णा सिंह के खिलाफ साबित होता है। तथापि, अभियोजन पक्ष ने यह स्थापित किया कि अपीलकर्ता कृष्णा सिंह, बीरबल चौधरी, श्याम बिहारी पासवान, अंगद कोइरी, जवाहर कोइरी, रामाश्रय कोइरी और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों अर्थात् रामवृक्ष कोइरी, हृदयानंद कोइरी, मंगला सिंह, रामदास कोइरी, सरोज सिंह और हरबंस राम सहित 12 अभियुक्त व्यक्तियों ने पीड़ितों का अपहरण किया और उन्हें अपनी अभिरक्षा में रखा तथा पीड़ितों को अपने सामान्य आशय की पूर्ति के लिए फिरौती का भुगतान करने के लिए यातना दी। इससे अदालत ने यह फैसला सुनाया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 364/34 के तहत 12 व्यक्तियों के खिलाफ अपराध अच्छी तरह से साबित और स्थापित किया गया है।

7) अपीलकर्ता जवाहर कोइरी को भारतीय दंड संहिता की धारा 412 के तहत भी अपराध के लिए आरोपित किया गया था। निचली अदालत ने उसके खिलाफ लगाए गए आरोप को इस तर्क पर ध्यान में रखा कि पीड़ित अजय शंकर मिश्रा की सोने की अंगूठी, जो अपहरण के दौरान आरोपी व्यक्ति द्वारा ली गई थी, उसके कब्जे से बरामद की गई थी। ऐसी परिस्थितियों में, आरोप को गवाहों के साक्ष्य, जब्ती सूची के साथ-साथ टीआईपी चार्ट द्वारा साबित और स्थापित किया गया था। अदालत ने आगे कहा कि अपीलार्थियों सहित 11 आरोपी व्यक्तियों में से एक सफेद मारुति जिप्सी के साथ लगभग 4 लाख रुपये की नकदी की डकैती करने के लिए मूल रूप से आईपीसी की धारा 397 के तहत आरोपित किया गया था, जिसका पंजीकरण नंबर बीआर 1 पी 2619 था, जो अभियोजन द्वारा अच्छी तरह से साबित किया गया था। अदालत ने अपीलकर्ता रामाश्रय कोइरी सहित अन्य अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 395 के तहत आरोप से मुक्त करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष शेष अभियुक्तों के

खिलाफ अपने मामले को स्थापित और साबित करने में विफल रहा है। हालांकि, अदालत ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में आईपीसी की धारा 395 के तहत शेष अपीलार्थियों के विरुद्ध अपराध अच्छी तरह से साबित और स्थापित किया गया। अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी के तहत अपराध के लिए अपीलकर्ताओं सहित आरोपी व्यक्तियों को इस निष्कर्ष के साथ बरी कर दिया कि भले ही यह पीडब्ल्यू-19, मामले के जांच अधिकारी के साक्ष्य में आया है कि आरोपी व्यक्तियों ने पीड़ितों का अपहरण करने की योजना बनाई थी, लेकिन यह तथ्य साबित नहीं हुआ और किसी भी अभियोजन गवाह के नेतृत्व में साक्ष्य से साबित नहीं हुआ। अभियोजन पक्ष द्वारा पीड़ित का अपहरण करने के लिए आरोपी व्यक्ति द्वारा कोई पूर्व सहमति साबित करने में विफल रहने पर, अदालत ने कहा कि धारा 120 बी के तहत अपराध किसी भी सबूत के बिना है।

8) निचली अदालत ने अपीलकर्ताओं कृष्णा सिंह और जवाहर कोयरी की आपराधिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए उन्हें मौत की सजा देना उचित माना और कहा कि उनके द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 364 ए/34 के तहत किए गए अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा अपर्याप्त होगी। तथापि, यह देखते हुए कि शेष अभियुक्तों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, न्यायालय ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 364 क/34 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आजीवन कारावास का दंडादेश दिया। आरोपी अपीलकर्ताओं में से कृष्ण सिंह और जवाहर कोइरी को भारतीय दंड संहिता की धारा 395 के तहत अपराध के लिए पहले ही सजा सुनाई जा चुकी थी, अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 412 के तहत अपराध के लिए उनके खिलाफ कोई अलग सजा नहीं देना उचित पाया।

9) उच्च न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से सामान्य निवेदन यह था कि मृत्यु का दंडादेश अपराध के अनुरूप और समाज के हित में था जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी। यह भी प्रस्तुत किया गया कि भले ही अदालत अपीलार्थी की मौत की सजा को बरकरार न रखे, निश्चित रूप से यह 14 साल की

अवधि के लिए आमतौर पर समझी जाने वाली आजीवन कारावास की सजा के लिए एक उपयुक्त मामला नहीं था।

10) उच्च न्यायालय ने अपने आक्षेपित निर्णय में यह मत व्यक्त किया कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पीड़ितों का अपहरण पूरी तरह से स्थापित हो चुका है। पीडब्ल्यू-17 के बयान में कथित अपहर्ताओं का पहला विवरण दिया गया है। उन्होंने बताया कि मोटरसाइकिलों में से एक पर पीछे बैठे व्यक्ति को उनके साथी नेता जी कहते थे। दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्ति के बाएं गाल पर तिल था। ये दोनों व्यक्ति क्रमशः पीडब्ल्यू-17 और पीडब्ल्यू-18 को जिप्सी से बाहर निकालते हैं। बाद में पैसों का बैग छीन लिया। बोलेरो से उतरने वाले एक अन्य व्यक्ति ने पीडब्ल्यू-20 को बाहर निकाला और उसे बोलेरो में धकेल दिया, उसके हाथ में एक राइफल थी। उन्होंने आगे बताया कि उनमें से एक सफेद बालों के रेशों के साथ एक झुकी हुई बाल रेखा के साथ बनाया गया था और उसने कुर्ता पजामा पहन रखा था। जिस व्यक्ति के पास राइफल थी वह गोरा रंग का था और उसकी औसत ऊंचाई थी जिसे उसके साथी बाबू साहब कहते थे। पीडब्ल्यू-17 ने आगे कहा कि 'वर्मा जी' के रूप में संदर्भित साथी ने अखबार के बंडलों में लिपटे पैसे के दो पैकेट बाहर निकालकर बोलेरो चलाने वाले व्यक्ति को 'बाबू साहब' के रूप में संबोधित किया और उसे वापस जाने के लिए कहा, जो उसने किया, दूसरे द्वारा चलाए गए जिप्सी के साथ। बोलेरो में यात्रा कर रहे अपहर्ता की पहचान नेता जी के रूप में हुई, जब पीडब्ल्यू-17 के मोबाइल फोन की घंटी बजी, जैसा कि पीडब्ल्यू-5 ने कहा था, कथित अपहर्ता ने कहा कि वह सभी का पिता था और उसने नंबर काट दिया।

11) उच्च न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि अपहरणकर्ता वाहन में लगभग पांच घंटे तक अपहरणकर्ताओं के साथ करीबी रूप से रहे थे और पीड़ितों को अभियुक्त व्यक्तियों की विशेषताओं और चेहरों की पहचान करने के लिए पर्याप्त अवसर था। अदालत ने कहा कि यह पूरी तरह से स्वाभाविक व्यवहार है और उनके साक्ष्य और पहचान के लिए बहुत विश्वसनीयता है। पीड़ितों की सदमा और पीड़ा निश्चित रूप से अपहर्ताओं की पहचान और विशेषताओं का कारण बनी पीड़ितों के मन में एक छाप के रूप में अंकित है जब उन्होंने कहा कि वे स्पष्ट रूप से उनकी पहचान कर सकते हैं।

अदालत ने आगे कहा कि ड्राइवर (पीडब्ल्यू-18), जिसे अपहरण के अगले दिन सोनबरसा पेट्रोल पंप के पास एक गवाह के रूप में रिहा किया गया था, ने पहली रात को सिमरी ग्राम में बंधक बनाकर रखा गया था। अपनी रिहाई पर, उसने कहा कि वह पुलिस के साथ गया था और उन्हें अपहरण का स्थान और वह स्थान दिखाया जहां उसे कैद में रखा गया था और अंततः रिहा कर दिया गया था। इस बात की पुष्टि पहले जांच अधिकारी पीडब्ल्यू-8 के साक्ष्य से हुई। पीडब्ल्यू-17 ने उन स्थानों का एक ग्राफिक विवरण दिया था, जहां उन्हें और पीडब्ल्यू-20 को लगभग 52 दिनों तक कैद रखा गया था, जिसमें पुलिस जांच के दौरान पीडब्ल्यू-19 द्वारा पुष्टि किए गए स्थलों की पहचान करना शामिल था।

12) उच्च न्यायालय ने प्रदर्शनी 8 के आधार पर की गई फिरौती की मांग पर भी चर्चा की, जो बंदी के दौरान पीडब्ल्यू-17 द्वारा लिखा गया और पीडब्ल्यू-20 द्वारा हस्ताक्षर किया गया पत्र है, जिसमें पीडब्ल्यू-5 से फिरौती की राशि का भुगतान करने और उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। फिरौती की मांग पीडब्ल्यू-5 के बीच बातचीत से भी स्थापित हो गई जब आरोपी अपीलकर्ता जवाहर कोइरी और सुरेश कोइरी ने फोन नंबर 9430029994 से खुद को पहचाना जिसे अपहरणकर्ताओं के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए भेजा गया था। 50 लाख रुपये की फिरौती की मांग की गई और उन्होंने आगे कहा कि वे फिरौती का दावा करने के लिए अपनी बंदी के सबूत के रूप में पीडब्ल्यू-17 की अंगूठी और एक पत्र (प्रदर्शनी 8) भेज रहे थे। मोबाइल फोरेंसिक साक्ष्य, जिसे जांच के दौरान रिकॉर्ड पर लाया गया था, यह भी दर्शाता है कि एक कॉल किया गया था जो साबित करता है कि वास्तव में फिरौती की मांग की गई थी। अदालत ने आगे बताया कि वर्तमान मामले में अपहरण का कार्य व्यक्तिगत खिलाड़ियों को सौंपी गई अलग-अलग भूमिकाओं के साथ रसद की सावधानीपूर्वक योजना का परिणाम था। एक बार फिरौती की मांग स्थापित हो जाने के बाद, चाहे वह वास्तव में भुगतान की गई हो या नहीं, वह अप्रासंगिक हो गई।

13) उच्च न्यायालय ने प्रत्येक अभियुक्त अपीलकर्ता को दिए गए दंडादेश के संबंध में अपने निर्णय में धारा 364 क के अंतःस्थापन पर चर्चा की जो देश में अपराध

के बदलते परिदृश्य का परिणाम था। अदालत ने अपराध की सहज और दोषरहित प्रकृति को इंगित किया, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आरोपी व्यक्ति नौसिखिया नहीं थे। धन तक त्वरित पहुंच प्राप्त करने की एकमात्र लालसा के साथ, अभियुक्त व्यक्तियों ने, जो अन्यथा कंगाल या भिखारी नहीं थे, एक संगठित आपराधिक असामाजिक गतिविधि को अंजाम दिया, जहां ऐसे लोग नहीं कर सकते थे। पुनः पुष्टि करने के लिए उत्तरदायी होना चाहिए क्योंकि वे समाज के लिए एक खतरा हैं। बदलते समय से निपटने में सक्षम होने के लिए, कानून को विकसित करने की आवश्यकता है और इस इरादे के साथ, अदालत ने इस अपराध के लिए आजीवन कारावास के प्रावधान पर चर्चा की। यह धारा उपहति कारित करने के लिए धमकी और वास्तविक उपहति से उपहति की आशंका के लिए उक्त दंड का उपबंध करती है। यह मानते हुए कि उक्त धारा को धारा ३१९ तक सीमित किए बिना अलगाव में पढ़ा जाना चाहिए, न्याय तब अभिभावी होगा यदि सभी अभियुक्त अपीलार्थियों को २० वर्ष का प्रतिवेदन दिया गया था। दो अभियुक्त अपीलार्थियों अर्थात् कृष्णा सिंह और जवाहर कोइरी के संबंध में, जिन्हें मृत्युदंड दिया गया था, न्यायालय ने तर्क दिया कि इन दो अपीलार्थियों के लिए बढ़े हुए दंडादेश के लिए उपबंधित एकमात्र औचित्य उनके आपराधिक पूर्ववृत्तों के कारण था, क्योंकि दो अपीलार्थियों की ओर से पीड़ितों को मृत्यु या चोट पहुंचाने की धमकी देने या मृत्यु या बहुत कम चोट पहुंचाने वाले किसी भी कार्य के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं था। यह मानते हुए कि एक अलग सजा देने के लिए अन्य अपीलकर्ताओं के मामले से उनके मामले को अलग करने का कोई औचित्य नहीं है, और यह मानते हुए कि वर्गीकरण केवल आपराधिक पृष्ठभूमि के आधार पर नहीं किया जा सकता है, उच्च न्यायालय ने उन्हें अन्य अपीलकर्ताओं के साथ 20 साल के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई।

14) स्पष्टता के लिए, हम सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा विचारण के परिणाम के संबंध में स्थिति का सारांश दे सकते हैं:

इस प्रश्नगत दो आरोपपत्र दायर किए गए थे, जिनका संक्षिप्त वर्णन ऊपर किया गया है, जिसमें तीन व्यक्तियों (पीडब्ल्यू-17, पीडब्ल्यू-18 और पीडब्ल्यू-20)

का अपहरण किया गया था। दोनों मामलों को मिला दिया गया जिसमें 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाया गया। निचली अदालत ने तीन व्यक्तियों प्रभावती देवी (ए-2), लाल मोहर सिंह (ए-3) और राजबहादुर सिंह उर्फ चुन्नू सिंह (ए-4) को सभी आरोपों से बरी कर दिया। शेष 12 व्यक्तियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी के तहत लगाए गए षड्यंत्र के आरोप से बरी कर दिया गया। कृष्ण सिंह (ए-1) और जवाहर कोइरी (ए-5) को आई. पी. सी. की धारा 364 ए/34 और धारा 395 के तहत अपराध करने के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। अपील में, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा दर्ज इन अभियुक्त व्यक्तियों की दोषसिद्धि को बरकरार रखा है। तथापि, ए-1 और ए-5 के मृत्युदंड को लघुकृत किया जाता है और उसके स्थान पर 20 वर्ष का कठोर कारावास प्रतिस्थापित किया जाता है। अन्य सिद्धदोषियों के मामलों में भी आजीवन कारावास की सजा को 20 वर्ष का कठोर कारावास तक संशोधित किया गया है। इसकी स्थिति नीचे दिए गए सारणी से प्रदर्शित होता है।-

आरोपी	नाम	आरोपित	निचली अदालत द्वारा दोषसिद्धि	निचली अदालत द्वारा दोषसिद्धि और दंड	उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि
1	कृष्णा बिहारी सिंह @ कृष्णा सिंह	364 ए/34, 120 बी, 395, 412/34	364 ए/34, 395, 412	मृत्यु और 10 साल कठोर कारावास	इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इसे बढ़ाकर 20 वर्ष किया गया।
2.	प्रभावती देवी	412/34	बरी कर दिया गया	X	X
3.	लाल मोहर सिंह	412/34	बरी कर दिया गया	X	X
4.	राजबहादुर सिंह @ चुन्नू सिंह	412/34	बरी कर दिया गया	X	X
5.	जवाहर कोइरी उर्फ जवाहर सिंह उर्फ नेता जी	364 ए/34, 120 बी, 395, 412	364 ए/34, 395, 412	मृत्यु और 10 साल कठोर कारावास	इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इसे बढ़ाकर 20 वर्ष किया गया।
6.	श्याम बिहारी पासवान	364 ए/34, 120 बी, 395	364 ए/34, 395	आजीवन और 10 साल कठोर कारावास	20 साल

आरोपी	नाम	आरोपित	निचली अदालत द्वारा दोषसिद्धि	निचली अदालत द्वारा दोषसिद्धि और दंड	उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि
7.	रामवृक्ष कोइरी	364 ए/34, 120 बी, 395	364 ए/34	आजीवन	20 साल
8.	हरबंस राम	368,412	364 ए/34	आजीवन	20 साल
9.	अंगद कोइरी	364 ए/34, 120 बी, 395	364 ए/34, 395	आजीवन और 10 साल कठोर कारावास	20 साल
10.	हिरदयानंद कोयरी	364 ए/34, 120 बी, 395	364 ए/34	आजीवन	20 साल
11.	मंगला सिंह	364 ए/34, 120 बी, 395	364 ए/34	आजीवन	20 साल
12.	सरोज सिंह	364 ए/34, 120 बी, 395	364 ए/34	आजीवन	20 साल
13.	बीरबल चौधरी @मुखिया जी	364 ए/34, 120 बी, 395	364 ए/34, 395	आजीवन और 10 वर्ष	20 साल
14.	रामाश्रय कोइरी	364 ए/34, 120 बी, 395	364 ए/34	आजीवन	20 साल
15.	रामदास कोयरी	364 ए/34, 120 बी, 395	364 ए/34	आजीवन	20 साल

15) उपर्युक्त 12 व्यक्तियों में से जिनकी दोषसिद्धि उच्च न्यायालय द्वारा कायम रखी जाती है, 11 व्यक्तियों ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। रामदरश कोयरी (ए-15) ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती नहीं दी है। इन 11 दोषसिद्ध व्यक्तियों की दांडिक अपीलों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

1.	आपराधिक अपील संख्या 701/2012	बीरबल चौधरी
2.	आपराधिक अपील संख्या 702/2012	श्याम बिहारी पासवान

3.	आपराधिक अपील संख्या 703-704/2012	जवाहर कोयरी
4.	आपराधिक अपील संख्या 705/2012	रामाश्रय कोइरी
5.	आपराधिक अपील संख्या 706/2012	(i) रामवृक्ष कोइरी (ii) हृदयानंद कोइरी (iii) मंगला सिंह (iv) सरोज सिंह
6.	आपराधिक अपील संख्या 707/2012	कृष्ण बिहारी सिंह
7.	आपराधिक अपील संख्या 708/2012	अंगद कोइरी
8.	आपराधिक अपील संख्या 1858/2013	हरबंस राम

16) श्री बसंत, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने 2012 की आपराधिक अपील संख्या 701, श्री उपाध्याय, वरिष्ठ अधिवक्ता ने 2012 की आपराधिक अपील संख्या 702, 2012, की अपील संख्या 705, 2012 की अपील संख्या 706 और 2012 की 708 पर तर्क दिया, जबकि सुश्री निरंजना सिंह और श्री टी. महिपाल, अधिवक्ताओं ने 2012 की आपराधिक अपील संख्या 707 और 2013 की 1858 पर तर्क दिया। राज्य की ओर से पेश अधिवक्ता श्री गोपाल सिंह ने विभिन्न अपीलार्थियों के वकील द्वारा दी गई दलीलों का जवाब दिया। सूचना देने वाले की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर. दास ने अभियोजन पक्ष का समर्थन किया।

17) जैसा कि ऊपर बताया गया है, यद्यपि इन अपीलार्थियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी के अधीन षड्यंत्र का आरोप भी विरचित किया गया था, सत्र न्यायालय ने उन्हें इस आरोप से बरी कर दिया। इस प्रकार, साजिश साबित नहीं हुई है। हालांकि, उपर्युक्त आपराधिक कृत्यों के पीछे साझा मंशा सिद्ध हो चुकी है। इस पृष्ठभूमि में, हम प्रत्येक अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत बचाव के अभिवाक की जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं, यह पता लगाने के लिए कि क्या उनकी दोषसिद्धि उचित है या नहीं।

18) श्री बसंत ने अपीलार्थी बीरबल चौधरी (ए-13) की ओर से बहस करते हुए तीन मोर्चों पर अपना प्रतिवेदन दिया, नामतः

(i) ए-13 को फंसाने के लिए कोई कानूनी साक्ष्य नहीं है।

(ii) भारतीय दंड संहिता की धारा 364 क के तहत लगाए गए आरोप पूरी तरह निराधार थे।

(iii) सजा को बढ़ाकर 20 वर्ष करना आर. आई. कानूनी रूप से अस्वीकार्य था।

19) पहले पहलू पर, श्री बसंत ने प्रस्तुत किया कि आरोप उन तीन व्यक्तियों के अपहरण से संबंधित थे जिन्होंने न्यायालय में पी डब्लू एस-17,18 और 20 के रूप में अभिसाक्ष्य दिया था लेकिन उनमें से किसी ने भी न्यायालय में ए-13 की पहचान नहीं की थी। इतना ही नहीं, पीडब्ल्यू-17 और पीडब्ल्यू-20 ने पहले भी उसकी पहचान नहीं की थी और टीआईपी में भाग नहीं लिया था। हालांकि पी० डब्लू-18 को 11 दिसंबर, 2006 को टीआईपी में ले जाया गया था, उसने किसी अन्य व्यक्ति की पहचान 'मुखिया जी' के रूप में की। उनका कहना था कि बीरबल चौधरी को केवल इन अपहरण किए गए व्यक्तियों के बयान के आधार पर फंसाया गया था कि जब उन्हें कैद में रखा गया था, अपहरण के बाद, एक व्यक्ति को 'मुखिया' और ए-13 को 'मुखिया' के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा, उनके मुवक्किल के खिलाफ एक भी सबूत नहीं था और यहां तक कि पीडब्लू-18 ने 11 दिसंबर, 2006 को आयोजित टीआईपी में 'मुखिया' के रूप में किसी और की पहचान की और इस साक्ष्य का उपयोग बीरबल चौधरी के खिलाफ नहीं किया जा सका। 14 दिसंबर, 2006 को आयोजित एक अन्य टीआईपी का उल्लेख करते हुए, श्री बसंत ने प्रस्तुत किया कि हालांकि टीआईपी में, उन्होंने बीरबल चौधरी की पहचान की, लेकिन अदालत में उन्होंने उसकी पहचान नहीं की। इसके अलावा, ए-13 से कोई वसूली नहीं की गई। पूर्वोक्त आधार पर, उसका प्रतिवेदन था कि इस अपीलार्थी को फंसाने के लिए कोई कानूनी सबूत नहीं था।

20) इस संदर्भ में श्री बसंत का एक और निवेदन यह था कि दो आरोपपत्रों को समेकित करने से पहले, पहले आरोप पत्र में, 13 व्यक्तियों को 16 अप्रैल, 2007 को विचारण के लिए सुपुर्द किया गया था और दूसरे आरोप पत्र के अन्य दो व्यक्तियों को 15 सितंबर, 2007 को विचारण के लिए सुपुर्द किया गया था। हालांकि, 15 सितंबर, 2007 से पहले, आरोप पत्र से संबंधित मुकदमे में छह गवाहों में से पीडब्ल्यू-1 से

पीडब्ल्यू-6 की पहले ही जांच की जा चुकी है। दो आरोपपत्रों को समेकित करने के बाद, पीडब्ल्यू-1 से पीडब्ल्यू-6 की फिर से जांच की गई। हालांकि, इन गवाहों के बयान का उपयोग अपीलार्थी बीरबल चौधरी के साथ-साथ निचली अदालत द्वारा अपने फैसले में किया गया, जिसने बीरबल चौधरी के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

21) श्री बसंत ने उच्च न्यायालय के उस तर्क में भी गलती पाई जिसमें ए-13 को टीआईपी के दायरे में रखा गया है।

22) भा. दं. सं. की धारा 364 क पर पूर्वानुमानित तर्क को प्रदर्शित करते हुए, श्री बसंत का निवेदन था कि इस धारा के घटक विचारण के दौरान साबित नहीं किए जा सकते क्योंकि फिरौती की कोई मांग नहीं की गई थी क्योंकि न तो पी डब्ल्यू-5 और न ही पी डब्ल्यू-17 ने इस आशय को अभिसाक्ष्य दिया था। इस उद्देश्य के लिए, उन्होंने एफआईआर प्रथम सूचना प्रतिवेदन में लगाए गए आरोपों को पढ़ा, जिसमें उनके अनुसार, 'मुखिया जी' या 'फिरौती' का कोई संदर्भ नहीं था। विद्वत वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि इस आशय का केवल एक विश्वास व्यक्त किया गया था जो साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता था। उन्होंने पीडब्लू-18, पीडब्लू-9 (मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जिन्होंने टीआईपी का संचालन किया) और पीडब्लू-20 के बयानों के प्रासंगिक हिस्सों को भी पढ़ा, जिन्होंने अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि यह आरोप लगाया गया है कि अपहृत व्यक्तियों को ए-13 के घर में रखा गया था, इस आशय का कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं था क्योंकि घर का कोई महाजिर तैयार नहीं किया गया था और इस आशय का कोई साक्ष्य नहीं दिया गया था कि जहां अपहृत व्यक्तियों को रखा गया था, वह घर ए-13 का है। इस संबंध में, उसने यह भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया कि गवाहों, विशेष रूप से, पीडब्ल्यू-8, पीडब्ल्यू-18 और पीडब्ल्यू-19 ने अलग-अलग संस्करण दिए थे। इस प्रकार, उन्होंने तर्क दिया कि फिरौती की कोई मांग साबित नहीं हुई।

23) जहां तक दंड की कथित वृद्धि का संबंध है, विद्वान वरिष्ठ वकील ने धारा 386 के साथ-साथ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 401 के उपबंधों का उल्लेख किया और प्रस्तुत किया कि दंड बढ़ाने से पहले, एक नोटिस दिए जाने की आवश्यकता है जो

इस मामले में नहीं किया गया था और इसलिए, इस प्रकार 20 वर्ष का दंड देने के लिए संशोधन करने का आदेश कानून के अनुसार नहीं था। इस प्रस्तुति के लिए, उन्होंने अपने मामले को फैसले पर टिका दिया। इस न्यायालय के विकास यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य¹ जिसमें यह निम्नलिखित रूप में आयोजित किया जाता है:

“39. विस्तृत रूप से कहें तो संविधान के अनुच्छेद 71 और अनुच्छेद 161 के तहत प्रयोग की गई शक्ति सीमित अर्थों में न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी है, फिर भी न्यायालय इस तरह की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। जहां तक सीआरपीसी की धारा 433-ए के तहत वैधानिक शक्ति का संबंध है, इसे तब कम किया जा सकता है जब न्यायालय की यह राय हो कि तथ्य स्थिति कारावास की सजा की हकदार है जो एक निश्चित अवधि के लिए हो कि माफी की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस बात का समर्थन करने के लिए कई प्राधिकरण हैं कि माफी की शक्ति को कम करने और दोषी द्वारा माफी पर विचार करने के लिए आवेदन को दबाने के लिए निश्चित अवधि की सजा दी गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी विशेष तथ्य की स्थिति में, यह एक दंडात्मक आवश्यकता बन जाती है जो अधिकतम और न्यूनतम की अवधारणा के भीतर अनुमेय है। अधिकतम यानी मौत की सजा को लेकर कोई विवाद नहीं है। हालांकि, जहां तक अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता की प्रस्तुति का संबंध है, वह यह है कि न्यायालय आजीवन कारावास और कुछ नहीं कह सकते हैं। इसे इस तरह के जकड़जामा सूत्र में नहीं रखा जा सकता। न्यायालय, जैसा कि वर्तमान मामले में है, आजीवन कारावास से मृत्यु के दंडादेश को बढ़ाने की अपील पर विचार करते समय, निश्चित रूप से कह सकता है कि दोषी को एक विशिष्ट अवधि के लिए वास्तविक कारावास का सामना करना पड़ेगा। यह न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है और इस तरह की व्याख्या की अनुमति है।

यह उल्लेखनीय है कि न्यायालय न्यूनतम से कम दंड नहीं दे सकता है लेकिन अधिकतम से कम दंड दे सकता है। यह सजा देने के दायरे में आता है और संवैधानिक रूप से स्वीकार्य है।”

24) राज्य की ओर से पेश हुए विद्वत अधिवक्ता श्री गोपाल सिंह ने तर्क दिया कि ए-13 को फंसाने और दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत थे, जिस पर निचली अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा विधिवत ध्यान दिया गया था। उन्होंने नीचे के न्यायालयों के फैसलों के उन हिस्सों का उल्लेख किया जिसमें ए-13 की भागीदारी के साथ-साथ उनके खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए पेश किए गए सबूतों पर चर्चा की गई है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि ए-13 सहित आरोपी व्यक्तियों द्वारा फिरौती मांगने के आरोप को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत थे, जिसके आधार पर आईपीसी की धारा 364 ए के तहत आरोप विधिवत साबित किया गया था। जहां तक अपीलार्थी के तर्क का संबंध है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 401 के अधीन कोई सूचना दंडादेश के उपांतरण से पहले तामील नहीं की गई थी, उसका प्रतिवेदन था कि यह दंडादेश की वृद्धि का मामला नहीं था। इसके विपरीत, उच्च न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा को 20 वर्ष की सजा में बदल दिया था और इसे सजा में कमी के रूप में लिया जाना चाहिए क्योंकि इस न्यायालय के निर्णयों के अनुसार 'आजीवन कारावास' को पूरे जीवन के लिए कारावास के रूप में माना जाना चाहिए।

25) जैसा कि तथ्यों और घटनाओं के वर्णन के दौरान पहले ही उल्लेख किया गया है, तीनों व्यक्तियों का 20 नवंबर, 2006 को अपहरण कर लिया गया था। जबकि ड्राइवर चालक (पीडब्ल्यू-18) को 21 नवंबर, 2006 को रिहा किया गया था, अन्य दो अपहरणकर्ताओं को 52 दिनों की अवधि के लिए कैद में रखा गया था और उन्हें केवल 11 जनवरी, 2007 को रिहा किया गया था। इस मामले में मुखबीर अरुण कुमार मिश्रा (पीडब्ल्यू-5) ने 21 नवंबर, 2006 को रात 10 बजे लिखित रिपोर्ट दर्ज की थी, जिसके आधार पर औपचारिक एफआईआर प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज की गई थी, जिसे 22 नवंबर, 2006 को मजिस्ट्रेट को भेजा गया था। पीडब्ल्यू-5 और उसके चचेरे भाई राजू मिश्रा (पीडब्ल्यू-20) सीमेंट, लोहे के व्यवसाय में भागीदार थे और हिंदुस्तान लीवर की

डीलरशिप भी रखते थे। पीडब्लू-17 उनका कर्मचारी था जो रामगढ़ क्षेत्र में व्यापार सहयोगियों से पैसे एकत्र करने, बकाया राशि के लिए जिम्मेदार था और इसके लिए अक्सर यात्रा करता था। उस दिन सूचना देने वाले के चचेरे भाई राजू मिश्रा (पीडब्ल्यू-20) के साथ पीडब्ल्यू-17 सफेद जिप्सी पर सुबह 10 बजे बक्सर से रवाना हुआ था जिसे पीडब्ल्यू-18 चला रहा था। उस दिन, उन्होंने विभिन्न व्यक्तियों से लगभग 4 लाख रुपये एकत्र किए थे और लगभग 3.30 बजे बक्सर के लिए प्रस्थान किया: जिसकी सूचना मुखबिर को टेलीफोन के माध्यम से किया गया। वे 4.30 बजे रामपुर पहुँचे। जिसके बारे में उन्होंने मुखबिर को टेलीफोन पर बताया था, लेकिन उसके बाद कोई संपर्क नहीं हुआ। जिस तरीके से पीडब्लू-5/मुखबिर को उनके अपहरण के बारे में पता चला, जैसा कि उसने अपनी शिकायत में पहले ही उल्लेख किया है। उसी दिन रात 10 बजे अपनी लिखित रिपोर्ट में, मुखबिर ने कहा था कि वह आश्चस्त था कि अपहरण फिरौती के लिए किया गया था। अभियोजन पक्ष ने 22 गवाहों से जिरह की। आरोपियों ने कुल 9 गवाहों से जिरह की। अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, पीड़ितों को उनके अपहरण के बाद, सिमरी ग्राम में जवाहर कोइरी @नेता जी (ए-5) के घर में रखा गया था और उसके बाद उन्हें ग्राम भानपुर और फिर गंज भरसरा में स्थानांतरित कर दिया गया था जहां उन्हें बीरबल चौधरी उर्फ मुखिया जी (ए-13) के घर में रखा गया था। वहां से उन्हें दिलहुआ, भाभनी और बाराडीह ग्राम ले जाया गया। इस आंदोलन को आरोपी के मोबाइल संस्करणों ग्राम स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि उन्होंने समय-समय पर बताया है। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) कि ये सभी गांव कोचास ए द्वारा पहचाने गए एक मोबाइल टावर के स्थान के भीतर आते हैं।

26) इस परिपेक्ष्य में, हम बीरबल चौधरी की भूमिका की जांच करते हैं। उसके खिलाफ साक्ष्य यह है कि पीड़ितों ने पाया कि ए-13 को अन्य लोगों द्वारा मुखिया जी के रूप में संदर्भित किया गया था। दूसरा प्रमाण जो पी० डब्लू-17 ने प्रस्तुत किया वह उसका परिचय पत्र है तथा अपहृतों को उसके घर में कुछ दिनों के लिए रखा गया था। सवाल यह है कि क्या उपरोक्त पहलुओं पर ठोस सबूत थे।

27) पीडब्लू-17, हालांकि टीआईपी में भाग नहीं लिया था, अपने बयान के लिए अदालत में आया था। उस दिन, उन्होंने अदालत में एक स्पष्ट बयान दिया कि हालांकि अन्य आरोपी व्यक्ति अदालत में मौजूद थे, लेकिन उन्हें अदालत में बीरबल चौधरी नहीं मिला। इससे पता चलता है कि पीडब्लू-17 बीरबल चौधरी की पहचान कर सकता था और जब उसने पाया कि वह उस दिन अदालत में उपस्थित नहीं था, तो उसने विशेष रूप से इस आशय का उल्लेख किया। पीडब्लू-17 फिर से 28 नवंबर, 2007 को अदालत में पेश हुआ। उस दिन बीरबल चौधरी अदालत में उपस्थित थे। पीडब्लू-17 ने उसकी विधिवत पहचान की और उल्लेख किया कि उसे ए-13 के घर में रखा गया था, जो गंज भरसारा का मुखिया था। इस पर संज्ञान लेते हुए, उच्च न्यायालय ने स्पष्ट टिप्पणी की है कि ए-13 ने न तो उक्त पहचान को विवादित किया और न ही इस पर प्रतिपरीक्षा में कोई सवाल उठाया। अपीलार्थी के विद्वत वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह दलील देकर कुछ लाभ लेने की मांग की है कि यद्यपि पी डब्लू-१८ ने १४ दिसंबर, २००६, पर न्यायालय में किए गए टीआईपी में ए-१३ की पहचान की थी, लेकिन उसने उसकी पहचान नहीं की थी। हालांकि, इस प्रक्रिया में किस बात की अनदेखी की जाती है कि वह मुकदमे के दौरान पलट गया था और इस तथ्य पर उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित तरीके से चर्चा की गई है:

“35. पी. डब्ल्यू. 18, इसी प्रकार एक वर्ष के पश्चात् साक्ष्य देना रात्रि 9 बजे अपहरण और मोबाइल वार्तालाप के कथन पर पी. डब्ल्यू. 17 के संगत था। उन्होंने पुलिस को रिहाई से पूर्व अपहरण का स्थान और परिरोध का स्थान दिखाने की पुष्टि की। गवाह ने अपहरण के दौरान इस्तेमाल की गई राइफल की पहचान की और टी. आई. पी. में अपनी मखमली रंग की सीट से बोलेरो की पहचान की और एक अभियुक्त बीरबल चौधरी की भी पहचान की, लेकिन अपनी सुरक्षा से संबंधित मुकदमे में अपीलकर्ता की पहचान के दौरान वह पलट गया, जैसा कि उसकी प्रतिपरीक्षा के कंडिका 13 में उसके बयान से बहुत स्पष्ट है।”

28) उपर्युक्त परिस्थिति में, न्यायालय में ए-13 की पहचान करने से इनकार करने वाले पीडब्लू-18 के आचरण पर अधिक विश्वास नहीं किया जा सकता है। टीआईपी के दौरान, उसने पहचान की थी और यह टीआईपी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (पीडब्ल्यू-9) की उपस्थिति में आयोजित किया गया था, जिन्होंने स्पष्ट रूप से पूर्वोक्त प्रभाव को अभिसाक्ष्य दिया था। इसके अलावा, पीडब्लू-17 के बयान के रूप में पर्याप्त सबूत पेश किए गए हैं (जिन्हें नीचे के दोनों न्यायालयों द्वारा विश्वसनीय माना जाता है) कि उन्हें ए-13 के घर में रखा गया था। उच्च न्यायालय के निर्णय में इस अपीलार्थी के बारे में विनिर्दिष्ट चर्चा निम्नलिखित रूप में चलती है:

"58. अपीलकर्ता बीरबल चौधरी को भारतीय दंड संहिता की धारा 364 ए/34 और 395 के तहत दोषी ठहराया गया है। और आर. आई. को आजीवन कारावास और दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। पी. डब्ल्यू. 18 द्वारा टी. आई. पी. में उसकी पहचान की गई है। यह याद रखना होगा कि गवाह एक ड्राइवर था जो पीडब्लू 5,17 और पीडब्लू 20 के रोजगार में अपनी आजीविका कमा रहा था। अभियुक्त की पहचान करने में उसकी रुचि स्पष्ट रूप से सीमित थी और वह स्पष्ट रूप से अपनी सुरक्षा के बारे में चिंतित था जब वह पूर्वोक्त गवाहों के रोजगार में नहीं रह सकता था। अपीलार्थी की पहचान ग्राम गंजभरसरा के मुखिया के रूप में की गई, जहां पीड़ितों को दिलहुआ ग्राम ले जाने से पहले 22.11.2006 की रात को रखा गया था। पी. डब्ल्यू. 17 ने 22 नवम्बर, 2007 को न्यायालय में गोदी में उपस्थित अन्य अभियुक्तों को मान्यता देते हुए कहा कि मुखिया जी न्यायालय में उपस्थित नहीं थे। यह और कुछ नहीं बल्कि साक्षी की पुष्टि द्वारा अभियुक्त की सकारात्मक पहचान है कि वह अभियुक्त की शारीरिक विशेषताओं को पहचानता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें ग्राम गंजभरसरा के मुखिया के घर में रखा गया था। पी. डब्ल्यू. 18 के बयान से यह स्पष्ट है कि टी. आई. पी. के

दौरान अपीलकर्ता को मान्यता देने के बावजूद वह फिर से यह कहते हुए न्यायालय में सुरक्षित रहना पसंद करता है कि उसने कभी भी किसी शरीर को मान्यता नहीं दी और वह आज भी ऐसा नहीं करता है। अपीलार्थी का घर कारावास के स्थानों में से एक था, जिसे प्रथम जांच अधिकारी पी डब्लू 8 को पी डब्लू 18 द्वारा दिखाया गया था, कारावास के उन स्थानों में से एक के रूप में जहां पीड़ितों को रात में उसे रिहा करने से पहले दूसरे दिन शाम को स्थानांतरित किया गया था। गवाह ने टी. आई. पी. के दौरान कहा था कि अपीलकर्ता वह व्यक्ति था जिसने उसे जिप्सी से खींच कर बोलेरो में धकेल दिया था। यह स्पष्ट रूप से पी डब्लू 17 के साक्ष्य के साथ मेल खाता है, जिन्होंने कहा कि पी डब्लू 18 को जिप्सी से बाहर निकाला गया और बोलेरो में धकेल दिया गया। स्पष्ट रूप से अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित, गवाह ने 11.12.2006 को टी. आई. पी. डब्ल्यू. 17 में अपीलकर्ता की पहचान नहीं की, जिसमें उसने ट्रायल शुरू होने के बाद अपने दरवाजे पर रात्रि दस्तक देने के अपने बयान में कहा है। लेकिन पी. डब्ल्यू. 18 को अपनी सुरक्षा का आश्वासन मिलने के बाद ही उसने फिर से साहस जुटाया, एक नया आवेदन दायर किया और मुश्किल से तीन दिन बाद 14.12.2006 को अपीलकर्ता की पहचान की। यह अपीलार्थी का मामला नहीं है कि गवाह को 11.12.2006 से 14.12.2006 के बीच उससे मिलने का अवसर मिला था। अपीलार्थी ने सीआर. संशोधन सं. 2007 वर्ष संख्या 2 सत्र न्यायाधीश, बक्सर के समक्ष उसी के विरुद्ध 2007 की धारा 2 के अधीन और जिसे 16 जनवरी, 2008 को खारिज कर दिया गया था। अपीलार्थी ने मामले को अंतिम रूप देने के लिए बर्खास्तगी पर सवाल नहीं उठाया। अपीलार्थी का अपनी पहचान में विवाद पर जोर जब पी डब्लू १८ उसे गेहूं के रंग का वर्णन करता है और पी. डब्ल्यू. 17 उसे निष्पक्ष के रूप में वर्णित करता है। गोरी

और गोरी भारतीय त्वचा में ज्यादा अंतर नहीं है, जो यूरोपीय त्वचा से अलग है। पी. डब्ल्यू. 8,17,18 और 19 ने लगातार कहा था कि पीड़ितों को अपीलार्थी के घर में रखा गया है, जो अपीलार्थी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में विवादित नहीं है, जब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 317 के तहत कई तिथियों पर अपनी याचिकाओं में खुद को 'मुखिया' के रूप में वर्णित करता है। इसलिए अपहरण और बंदी बनाने में उसकी संलिप्तता साबित हो चुकी है।”

29) विशेष रूप से श्री बसंत की दलीलों को ध्यान में रखते हुए, हमें उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए पूर्वोक्त निष्कर्ष से विचलित होने का कोई कारण नहीं मिलता है। हम इस बात से सहमत हैं कि पीड़ितों के अपहरण और बंदी बनाने में बीरबल चौधरी की संलिप्तता पूरी तरह से स्थापित है।

30) जहां तक फिरौती की मांग का संबंध है, यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि पहले ही दिन, जब सूचना देने वाले ने अपनी लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी, तो उसने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि वह आश्वस्त था कि अपहरण फिरौती के लिए किया गया था। एक अन्य पहलू जो उच्च न्यायालय द्वारा रेखांकित किया गया है, वह यह है कि अपहृत किए गए तीन व्यक्तियों में से चालक (पीडब्ल्यू-18) को अगले ही दिन रिहा कर दिया गया था, जबकि अन्य को 52 दिनों के लिए कैद में रखा गया था। इन पीड़ितों के साथ किए जाने वाले इस अलग-अलग व्यवहार को उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित तरीके से अपने फैसले में रेखांकित किया है:

“30. 17, 18 और 20 अपहरण के शिकार थे। पी. डब्ल्यू. 17 और 20, मुखबिर के व्यापारियों और रिश्तेदारों को 52 दिनों के बाद 11.1.2007 को कैद से रिहा कर दिया गया था, जबकि पी. डब्ल्यू. 18, चालक को रात में अपहरण के अगले दिन छोड़ दिया गया था। अंतर बहुत स्पष्ट है। पी. डब्ल्यू. 18 फिरौती के लिए अपहरण के लायक नहीं था।”

31) यह भी रिकॉर्ड पर आया है कि 27 नवंबर, 2007 को प्रदर्शनी-8 पीडब्ल्यू-20 द्वारा हस्ताक्षर किए गए बंदी के दौरान पीडब्ल्यू-17 द्वारा लिखा गया पत्र है जिसमें पीडब्ल्यू-5 से फिरौती की राशि का भुगतान करने और उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। फिरौती की मांग पीडब्ल्यू-5 के बीच बातचीत से स्थापित होती है, जब आरोपी जवाहर कोइरी और सुरेश कोइरी ने अपहरणकर्ताओं से संपर्क स्थापित करने के लिए मोबाइल फोन नंबर 9430029994 से कॉल करके अपनी पहचान की और 50 लाख रुपये की फिरौती की मांग की और आगे कहा कि वे फिरौती का दावा करने के लिए अपनी बंदी के प्रमाण में पीडब्ल्यू-17 की अंगूठी और उनके द्वारा एक पत्र (प्रदर्शनी-8) भेज रहे थे। प्रदर्शनी-8 में कहा गया है कि पीडब्ल्यू-5 को जल्द से जल्द उन्हें छुड़ाने की व्यवस्था करनी चाहिए। 28 नवंबर, 2006 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 63 (बी) में दी गई व्यवस्था के अनुसार टेलीफोन अधिकारियों से जांच के दौरान प्राप्त मोबाइल फोरेंसिक साक्ष्य से पता चलता है कि उपरोक्त नंबर से की गई कॉल से मोबाइल नंबर 9934848065 पर कॉल की गई थी। पीडब्ल्यू-21 स्पष्ट रूप से साबित करता है कि फिरौती की मांग वास्तव में की गई थी। अन्यथा भी, यह अपीलार्थियों का बचाव नहीं है कि झूठे निहितार्थ के लिए पीड़ितों और अपीलार्थियों के बीच कोई दुश्मनी थी। एक बार अपहरण की पुष्टि हो जाने के बाद, निश्चित रूप से अपहर्ताओं ने इस तरह की सुनियोजित तरीके से चर्चा नहीं की, न ही छिपकर खेलने के लिए या केवल पीड़ितों को किसी व्यावसायिक विवाद से डराने के लिए या किसी अन्य कारण से उन्हें किसी विशेष कार्रवाई से दूर रहने के लिए मजबूर किया। वर्तमान तरीके से अपहरण का एक कार्य व्यक्तिगत खिलाड़ियों को अलग-अलग भूमिकाओं के साथ संचारतंत्र की सावधानीपूर्वक योजना बनाने का परिणाम है। इसलिए, फिरौती की मांग स्पष्ट रूप से स्थापित हो गई है। वास्तव में इसका भुगतान किया गया था या नहीं, यह अप्रासंगिक है।

32) धारा 364 क निम्नानुसार है:

“ऐसे अपहरण या अपहरण के बाद जो कोई किसी व्यक्ति का अपहरण या अपहरण करता है या किसी व्यक्ति को हिरासत में रखता है और

ऐसे व्यक्ति को मृत्यु या चोट पहुंचाने की धमकी देता है, या उसके आचरण से यह उचित आशंका पैदा होती है कि ऐसे व्यक्ति को सरकार या (किसी विदेशी राज्य या अंतरराष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति) को कोई कार्य करने या उससे परहेज करने के लिए मजबूर करने के लिए मौत की सजा दी जा सकती है या आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है, और जुर्माने का भी भागी होगा।”

33) मल्लेशी बनाम कर्नाटक राज्य² में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित अधिकथित किया है। धारा 364 क के अधीन अपराध करने की स्थापना के लिए संतुष्ट किए जाने की आवश्यकता वाले अवयवों पर यह अभिनिर्धारित किया गया है कि:

“धारा 364-ए के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए यह आवश्यक है कि इसे साबित किया जाए:

- (1) ऐसे अभियुक्त ने किसी व्यक्ति का अपहरण किया हो;
- (2) ऐसे अपहरण और अपहरण के बाद उसे निरोध में रखा गया; और
- (3) ऐसे अपहरण जो फिरौती के लिए किया गया हो।”

34) जहां तक फिरौती के लिए अपहरण के संघटक का संबंध है, न्यायालय ने निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान किए:

“आखिरकार यह सवाल तय किया जाना था कि इसका इरादा क्या था? क्या यह फिरौती की मांग थी? मांग करने का कोई निश्चित तरीका नहीं हो सकता है। फिरौती का भुगतान कौन करता है, यह कोई तय करने वाला तथ्य नहीं है।”

35) जहां तक अपहरण का संबंध है, इस बारे में कोई गंभीर विवाद नहीं है। हम पाते हैं कि फिरौती की मांग अभियोजन पक्ष द्वारा विधिवत साबित कर दी गई है।

36) श्री बसंत के अंतिम तर्क में भी योग्यता का अभाव है। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि सत्र न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 364 ए/34 के तहत दोषसिद्धि के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस न्यायालय द्वारा स्वामी श्रद्धानंद (2) @मुरली मनोहर मिश्रा बनाम कर्नाटक राज्य³ ऐसे तीन मामले में कहा गया था कि आजीवन कारावास का अर्थ पूर्ण आजीवन कारावास होगा न कि 14 वर्ष का दंड जो कुल मिलाकर हो सकता है जो असंतुलित या अपर्याप्त है और इसे आजीवन दंड नहीं कहा जा सकता। विशेष रूप से इस निर्णय पर ध्यान देने के बाद, उच्च न्यायालय ने 20 साल के कारावास की सजा देना उचित समझा। यह न केवल अपीलार्थी या अन्य के मामले में किया गया था, जिन्हें निचली अदालत द्वारा आजीवन कारावास दिया गया था, बल्कि दो अन्य दोषियों, जिन्हें मृत्यु दंड दिया गया था, के मामले में भी उनकी सजा को घटाकर 20 साल कर दिया गया है। विकास यादव के मामले में इस न्यायालय का निर्णय अपीलार्थी के लिए कोई मदद नहीं है। उस मामले में, मुख्य मुद्दा आजीवन कारावास की माफी का था और पैरा 39 में टिप्पणियां उस संदर्भ में की गई थीं। अन्यथा, उस मामले के तथ्यों से पता चलता है कि निचली अदालत द्वारा आजीवन कारावास को कम से कम 25 वर्ष की क्षमा नहीं करने योग्य की नियत अवधि में परिवर्तित करना उस मामले के तथ्यों के लिए उचित माना गया था। हम उल्लेख कर सकते हैं कि संविधान पीठ के निर्णय को मुथुरामलिंगम और अन्य बनाम राज्य जो पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसमें स्वामी श्रद्धानंद के वाद के विचार वाद स्वीकृति प्रदान की गई कि आजीवन कारावास मतलब जीवनभर के लिए होता हो। जिस मुद्दे पर विचार किया गया, वह बिल्कुल अलग था। यह न्यायालय मुथुरामलिंगम और ओआरएस वी राज्य द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया पुलिस निरीक्षक⁴ ने स्वामी श्रद्धानंद के

3 (2008) 13 एससीसी 767

4 (2016) 8 एससीसी 313

मामले में लिए गए दृष्टिकोण को मंजूरी दी है कि आजीवन कारावास को ही आजीवन कारावास माना जाएगा।

37) जहां तक श्री बसंत, अपीलार्थी के विद्वत वरिष्ठ अधिवक्ता के तर्क का संबंध है, चार्जशीट के समेकन के बाद पीडब्लू-1 से पीडब्लू-6 की फिर से जांच पर पूर्वानुमान लगाया गया था, हम पाते हैं कि यह कदम अपीलार्थी के हित में उठाया गया था। प्रथम आरोप-पत्र में अपीलार्थी का नाम नहीं था और जब प्रथम आरोप-पत्र में पीडब्लू-1 से पीडब्लू-6 की जांच की गई थी, स्पष्ट रूप से, अपीलार्थी उपस्थित नहीं था। यही कारण है कि इन गवाहों से फिर से पूछताछ की गई और अपीलकर्ता को उनसे जिरह करने का पूरा मौका दिया गया। हम नहीं पाते कि पहली बार में जब इन गवाहों की जांच की गई तो उनके बयान का उल्लेख करके अपीलकर्ता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाला गया है क्योंकि दोनों अवसरों पर उनका बयान समान रहा है। इसलिए हमें इस तर्क में भी कोई औचित्य नहीं दिखता।

38) परिणामस्वरूप, हम 2012 की आपराधिक अपील संख्या 701 को खारिज करते हैं।

2012 की आपराधिक अपील संख्या 702

39) यह अपील श्याम बिहारी पासवान (ए-6) द्वारा दायर की गई है, जिन्हें आईपीसी की धारा 364 ए के साथ धारा 34 और आई पी सी की धारा 395 के तहत भी दोषी ठहराया गया है। ए-6 की ओर से बहस करते हुए श्री उपाध्याय ने प्रस्तुत किया कि उन्हें पी डब्ल्यू-17 की गवाही के आधार पर दोषी ठहराया गया है, जबकि चालक (पी डब्ल्यू-18) ने इसके विपरीत बयान दिया था। उन्होंने यह भी कहा कि जहां तक पीडब्ल्यू-20 का संबंध है, उन्होंने ए-6 का नाम नहीं लिया। उन्होंने यह भी सवाल किया कि पीडब्ल्यू-18 और पीडब्ल्यू-20 को छोड़कर केवल पीडब्ल्यू-17 ने ही टीआईपी के लिए क्यों बुलाया। उन्होंने यह भी कहा कि पीडब्ल्यू-17 पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। विद्वत अधिवक्ता द्वारा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को संबोधित ए-6 द्वारा 29 दिसंबर, 2006 को लिखे गए पत्र के आधार पर बहुत लाभ उठाने की मांग

की गई थी, जिसमें उसने न्यायिक हिरासत में रहते हुए उस पर अवैध यातना देने का आरोप लगाया था।

40) पीडब्लू-17 की गवाही पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है और जहां तक इस पहलू का संबंध है, हम अधिवक्ता के तर्क से सहमत नहीं हैं। उच्च न्यायालय ने इस टीआईपी को निर्दोष माना है और ए-6 की भूमिका पर निम्नलिखित तरीके से विचार किया गया है:

"56. अपीलार्थी को धारा 364 ए/34 और 395 I.P.C के तहत दोषी ठहराया गया है और R.I. को आजीवन कारावास और बाद वाले के तहत दस साल की सजा सुनाई गई है। पी. डब्ल्यू. 17 ने अपने साक्ष्य में कहा है कि जब उनके वाहन को रोका गया तो एक अपहर्ता मोटरसाइकिल से उतर गया और उसने पी. डब्ल्यू. 18 को जिप्सी से बोलेरो में धकेल दिया जिसके गाल पर एक तिल था। इसी तरह, जैसा कि अपीलार्थी कृष्ण बिहारी सिंह और जवाहर कोरी, पी. डब्ल्यू. 17 ने 05.02.2007 के परीक्षण पहचान परेड में इस अपीलार्थी की पहचान की। अपीलार्थी ने 18.12.2006 को आत्मसमर्पण किया और 19.12.2006 से 26.12.2006 तक पुलिस हिरासत में था। पी. डब्ल्यू. 17 और 20 को 11 जनवरी, 2007 को जारी किया गया था। अतः, जिन तर्कों के लिए साक्षी को अभियुक्त को देखने का अवसर मिला, जिसकी तस्वीर ली गई थी और जिसके लिए उसने मानव अधिकार आयोग आदि को लिखा था, तथ्यों के रूप में उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है, यह न्यायालय संतुष्ट है कि टी. आई. पी. में कोई विलंब नहीं हुआ है जिससे कि उसे दूषित किया जा सके। टी. आई. पी. में अभिकथित अवैधता के तर्क का कोई लाभ नहीं है और इस अपील में केवल सरलता है क्योंकि ऐसे कोई प्रश्न पी. डब्ल्यू. 9, मजिस्ट्रेट, जिसने टी. आई. पी. का संचालन किया, से प्रतिपरीक्षा में नहीं रखे गए थे। साक्षी ने

27.11.2007 को कठघरे में उपस्थित चार अभियुक्तों में से एक के रूप में अपीलार्थी का नाम लिया, जब उसने कहा कि उसने उपस्थित अन्य व्यक्तियों की पहचान नहीं की है और स्पष्ट अंतर किया।”

41) इस प्रक्रम पर यह उल्लेख करना दिलचस्प होगा कि जहां तक भा. दं. सं. की धारा 395 के अधीन दोष-सिद्धि का संबंध है, किसी वकील ने उस पर प्रश्न भी नहीं उठाया था क्योंकि इस संबंध में कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 395 डकैती के लिए दंड से संबंधित है। यह प्रावधान इसलिए लागू किया गया क्योंकि अपहर्ताओं की संख्या पांच से अधिक थी और उन्होंने अपहर्ताओं के कब्जे से धन लूट लिया था। यह स्वयं पीडब्ल्यूएस-17,18 और 20 के अपहरण की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त है। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पीडब्लू-19, जो इस मामले में जांच अधिकारी (आईओ) थे, ने विस्तार से बताया है कि उन्होंने किस तरह से जांच की, जिससे पता चलता है कि यह जांच के दौरान, आरोपी व्यक्तियों के नाम सामने आते रहे और तदनुसार जांच आगे बढ़ी। जहां तक पीडब्ल्यू-18 के बयान का सवाल है, हम पहले ही ऐसा कर चुके हैं। 2012 की आपराधिक अपील संख्या 701 पर विचार करते समय इस पर विचार किया, जो अपनी सुरक्षा के डर से मुकर गया था। दोहराव की कीमत पर, हम यह इंगित कर सकते हैं कि यद्यपि पी डब्लू-१८ ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १६१ के तहत दर्ज किए गए बयान के विपरीत अभिसाक्ष्य दिया था। इसके अलावा, अदालत में अपने बयान के तीन दिनों के भीतर, उसने साहस जुटाया जब उसे अपनी सुरक्षा का आश्वासन दिया गया और उसने एक नया आवेदन दायर किया और आरोपी व्यक्तियों की पहचान की। उच्च न्यायालय द्वारा बीरबल चौधरी के मामले पर विचार करते समय इस पहलू पर प्रकाश डाला गया है और उक्त भाग पहले से ही है ऊपर से निकाला गया है। सुमन सूद @कंवलजीत कौर बनाम राजस्थान राज्य⁵ पहचान परेड का महत्व, साक्ष्य के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में, निम्नलिखित तरीके से दिया गया:

“59. एआईआर 2007 उच्चतम न्यायालय 2774 (सुमन सूद @कंवलजीत कौर बनाम राजस्थान राज्य) में दंड संहिता की धारा 364 क के अधीन दोषसिद्धि थी। यह पैरा 41 में निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया: अभियुक्त की पहचान के संबंध में, दोनों न्यायालयों ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य पर विचार किया है और यह निष्कर्ष दर्ज किया है कि अभियुक्त की पहचान संदेह से परे स्थापित की गई थी। हम इस बात से भी संतुष्ट हैं कि पीडब्लू 9, पीड़ित राजेंद्र मिर्धा का साक्ष्य स्वाभाविक और प्रेरित आत्मविश्वास था। उसके साक्ष्य से पता चला कि 17 फरवरी, 1995 की सुबह उसका अपहरण कर लिया गया था और वह मुठभेड़ की तारीख 25 फरवरी, 1995 तक अर्थात् आठ-नौ दिनों तक अपहर्ताओं के साथ रहा। जाहिर है, इसलिए उनके साक्ष्य का अत्यधिक महत्व था। दोनों अदालतों द्वारा इस पर विश्वास किया गया और हमें नीचे की अदालतों के दृष्टिकोण में कुछ भी गलत नहीं दिखता है। यह सच है और अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा स्वीकार किया गया है कि आरोपियों की तस्वीरें टेलीविजन पर दिखाई गई थीं और समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की गई थीं। तथापि, इससे किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य विश्वसनीय हैं और न्यायालय अभियुक्त की पहचान के बारे में संतुष्ट है तो अभियोजन पक्ष पर यह उल्लेख किया गया है कि यदि अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य विश्वसनीय हैं और न्यायालय अभियुक्त की पहचान के बारे में संतुष्ट है। वह आधार भी, इसलिए, अपीलार्थियों के मामले को आगे नहीं ले जा सकता है। इस प्रकार यह संदेह से परे साबित होता है कि अभियुक्तों ने भारतीय दंड संहिता की धारा 343 और 120 बी के साथ पठित धारा 346 के साथ धारा 120 वीं के तहत दंडनीय अपराध किए थे।”

42) इस विधिक स्थिति को महाबीर बनाम दिल्ली राज्य⁶ वाले मामले में निम्नलिखित शब्दों में दोहराया गया:

“12. यह कहना सामान्य है कि मूल साक्ष्य न्यायालय में पहचान का साक्ष्य है। साक्ष्य अधिनियम की धारा ९ के स्पष्ट प्रावधानों के अलावा, कानून में स्थिति इस न्यायालय के फैसलों की एक सूची द्वारा अच्छी तरह से तय की गई है। तथ्य, जो अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान स्थापित करते हैं, साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के तहत प्रासंगिक हैं। पहली बार विचारण के दौरान केवल अभियुक्त व्यक्ति की पहचान का साक्ष्य उसकी स्वाभाविक रूप से कमजोर प्रकृति का है। इसलिए पूर्व परीक्षण पहचान का उद्देश्य उस साक्ष्य की विश्वसनीयता का परीक्षण करना और उसे मजबूत बनाना है। तदनुसार, पूर्व पहचान कार्यवाहियों के रूप में उन अभियुक्तों की पहचान के बारे में जो उनके लिए अजनबी हैं, न्यायालय में गवाहों की शपथ की पुष्टि की तलाश को सामान्यतः विवेक का एक सुरक्षित नियम माना जाता है। तथापि, विवेक का यह नियम अपवादों के अध्यधीन है, जब, उदाहरण के लिए, न्यायालय किसी विशिष्ट साक्षी से प्रभावित होता है, जिसके साक्ष्य पर वह ऐसे या अन्य संपुष्टि के बिना, सुरक्षित रूप से भरोसा कर सकता है। पहचान परेड जांच के चरण से संबंधित है और संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो जांच एजेंसी को अभियुक्त को परीक्षण पहचान परेड का दावा करने का अधिकार प्रदान करने के लिए बाध्य करता है। ये ठोस साक्ष्य नहीं हैं और ये परेड अनिवार्य रूप से संहिता की धारा 162 द्वारा शासित हैं। परीक्षण पहचान परेड आयोजित करने में असफलता न्यायालय में पहचान के साक्ष्य को अग्राह्य नहीं बनाएगी। ऐसी पहचान को कितना महत्व दिया जाना चाहिए, यह तथ्य न्यायालयों के लिए एक मामला होना चाहिए। उपयुक्त मामलों में यह स्वीकार कर सकता है कि पहचान का साक्ष्य

है, यहां तक कि पुष्टि पर जोर दिए बिना। (कांता प्रसाद बनाम दिल्ली प्रशासन (एआईआर 1958 एससी 350), वैकुंठम चंद्रप्पा और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (एआईआर 1960 एससी 1340), बुधसेन और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (एआईआर 1970 एससी 1321) और रामेश्वर सिंह बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य (एआईआर 1972 एससी 102) देखें।”

43) हम यह इंगित कर सकते हैं कि श्री दाष, मुखबिर के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया था कि मोतीलाल यादव बनाम बिहार राज्य⁷, रौनी उर्फ रोनाल्ड जेम्स अलवरीस और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य⁸ और सुरेश चन्द्र बाहरी और अन्य बनाम बिहार राज्य⁹ वाले मामले में निर्णयों का उल्लेख करके इस मामले में टीआईपी आवश्यक नहीं था। हालांकि, एक बार जब हम पाते हैं कि वर्तमान मामले में किए गए टीआईपी पर सही तरीके से भरोसा किया गया है, तो इस पहलू से निपटना आवश्यक नहीं है।

44) इस प्रकार, यह अपील भी खारिज की जाती है।

45) 2012 की आपराधिक अपील संख्या 705 रामाश्रय कोइरी (ए-14) द्वारा दायर की गई है और 2012 की आपराधिक अपील संख्या 706 चार दोषी व्यक्तियों, रामवृक्ष कोइरी (ए-7), हिरदयानंद कोइरी (ए-10), मंगला सिंह (ए-11) और सरोज सिंह (ए-12) द्वारा दायर की गई है। यह प्रस्तुत किया गया कि जहां तक इन व्यक्तियों का संबंध है, उनका नाम न तो पीडब्ल्यू-17 या पीडब्ल्यू-18 या पीडब्ल्यू-20 द्वारा और न ही पीडब्ल्यू-20 द्वारा लिया गया था। कोई टीआईपी आयोजित नहीं की गई थी और साथ ही साथ गवाहों द्वारा उनकी पहचान भी नहीं की गई थी। उनके खिलाफ एकमात्र आरोप यह था कि उन्होंने गिरफ्तारी के समय पीड़ित को खाना खिलाया था।

7 (2015) 2 एससी 647

8 (1998) 3 एससी 6

9 1995 सप (1) एससी 80

46) तथापि, ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन व्यक्तियों को भा. दं. सं. की धारा 34 की सहायता से भी दोषसिद्ध ठहराया जाता है। इन अपीलार्थियों के संबंध में, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित तरीके से उनके दंड की पुष्टि की है:

“67. अपीलकर्ता राम बृक्ष कोरी, हिरदे कोरी मंगला सिंह और सरोज सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 395 के तहत आरोप से बरी कर दिया गया है, लेकिन भारतीय दंड संहिता की धारा 364 ए/34 के तहत दोषी ठहराया गया है और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अपीलार्थियों को अपीलार्थी जवाहर कोरी के घर से 10.12.2006 को गिरफ्तार किया गया है। पी. डब्ल्यू. 19, जिन्होंने छापा मारा, ने कहा कि अपीलकर्ताओं ने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया। कहा जाता है कि वे अभियुक्तों को संचारतंत्र सहायता प्रदान करते रहे हैं कि उन्हें टी. आई. पी. में नहीं रखा गया है या अभियोजन पक्ष में उनकी पहचान प्रासंगिक नहीं है क्योंकि उन्हें किसी अभियुक्त के घर से पीड़ित के निरंतर परिरोध के साथ हिरासत में लिया गया था, जो ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा सकारात्मक रूप से साबित किया गया था, जब उनकी दोषसिद्धि उपर्युक्त अभियुक्त की सहायता करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 34 की सहायता से होती है, और आगे किसी भी सकारात्मक प्रत्यक्ष कार्य के सबूत की आवश्यकता के बिना केवल उपस्थिति पर्याप्त होगी। स्पष्ट रूप से वे ऐसे व्यक्ति थे जो अपीलार्थियों और पीड़ितों की भोजन तैयार करके और अन्यथा उनके कल्याण की देखभाल कर रहे थे। वर्तमान स्वरूप के संचालन में इस बात पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि कई खिलाड़ी अपनी-अपनी भूमिकाओं से जुड़े हुए हैं क्योंकि किसी व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि वह निष्पादन की सरलता के साथ अकेले ही प्रश्रुत कार्य करे।

68. अपीलकर्ता रामाश्रय कोरी और राम दाष कोइरी दिलहुआ ग्राम के राम दास कोरी को भारतीय दंड संहिता की धारा 364 ए/34 के तहत दोषी ठहराया गया है और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। उन्हें न तो टी. आई. पी. पर रखा गया है और न ही पी. डब्ल्यू. 17, 18 या 20 द्वारा उनकी पहचान की गई है। उनके खिलाफ सबूत आरोपी श्याम बिहारी पासवान के स्वीकारोक्ति में यह है कि पीड़ितों को दिलहुआ ग्राम में उनके घर में रखा गया था। संस्वीकृति का यह हिस्सा अपीलार्थियों की दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं होगा। लेकिन जब पी डब्लू 17 द्वारा पी डब्लू 19 को अपीलार्थियों के घर की पहचान उस स्थान के रूप में करने के साक्ष्य द्वारा इसकी पुष्टि की जाती है जहां उन्हें 22 नवंबर, 2006 की रात को गंजभरसरा से स्थानांतरित होने के बाद दिलहुआ ग्राम में बंदी बनाया गया था। उनके खिलाफ कमजोर सबूत अपने दोषसिद्धि को सही ठहराने के लिए पूरी तरह से मजबूत हो जाते हैं।”

47) यह तर्क देने की मांग की गई थी कि धारा 34 की सहायता गलत तरीके से वर्तमान मामले में ली गई थी और समर्थन में, विद्वत वकील निम्नलिखित को संदर्भित करता है। मोहन सिंह और एक अन्य बनाम पंजाब राज्य¹⁰ और अन्य के मामले, जहां यह था आयोजित किया गया:

“13. यह अनिवार्य रूप से हमें इस सवाल पर ले जाता है कि क्या अपीलकर्ता को धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया जा सकता है। धारा 149 की तरह, धारा 34 भी रचनात्मक आपराधिक दायित्व के मामलों से संबंधित है। यह उपबंध करता है कि जहां कई व्यक्तियों द्वारा सभी के सामान्य आशय को आगे बढ़ाने के लिए कोई आपराधिक कार्य किया जाता है, तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति उसी तरह से उस कार्य के लिए उत्तरदायी है जैसे कि वह अकेले उसके द्वारा

10 एयर 1963 एससीसी 174

किया गया था। धारा 34 द्वारा विहित प्रतिवादी आपराधिक दायित्व का आवश्यक घटक सामान्य आशय का अस्तित्व है। यदि प्रश्नगत समान आशय अभियुक्त व्यक्तियों को प्रेरित करता है और यदि उक्त समान आशय से आरोपित आपराधिक अपराध होता है तो उनमें से किसी एक द्वारा किए गए आपराधिक कार्य के लिए समान आशय साझा करने वाला प्रत्येक व्यक्ति रचनात्मक रूप से दायी है। जिस प्रकार एक ही समान उद्देश्य को साझा करने वाले व्यक्तियों का संयोजन एक गैर-कानूनी सभा की विशेषताओं में से एक है, उसी प्रकार समान आशय साझा करने वाले व्यक्तियों के संयोजन का अस्तित्व धारा 34 की विशेषताओं में से एक है। कुछ मायनों में दोनों खंड एक जैसे हैं और कुछ मामलों में वे एक-दूसरे को अतिक्षादित कर सकते हैं। किंतु, फिर भी, सामान्य आशय जो धारा 34 का आधार है, उस सामान्य उद्देश्य से भिन्न है जो किसी विधिविरुद्ध सभा की संरचना का आधार है। सामान्य इरादा सहमति से कार्यवाई को दर्शाता है और आवश्यक रूप से एक पूर्व-व्यवस्थित के अस्तित्व को स्थापित करता है और इसका अर्थ दिमाग की पूर्व बैठक होना चाहिए। यह देखा गया है कि जिन मामलों में धारा 34 लागू की जा सकती है, उनमें सभी अभियुक्त व्यक्तियों की ओर से कार्यवाई में भाग लेने के तत्व का खुलासा होता है। ये कार्य अलग-अलग हो सकते हैं, उनके चरित्र में अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन वे सभी एक ही समान इरादे से प्रेरित होते हैं। अब यह अच्छी तरह से निर्धारित किया गया है कि धारा 34 द्वारा अपेक्षित सामान्य आशय एक ही आशय या समान आशय से भिन्न है। जैसा कि प्रिवी काउंसिल द्वारा महबूब शाह बनाम किंग-एम्परर [72 आईए 148] में देखा गया है, धारा 34 के अर्थ के भीतर सामान्य इरादे का तात्पर्य एक पूर्व-नियोजित योजना से है, और धारा को लागू करने वाले अपराध के लिए अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए यह साबित किया जाना चाहिए कि आपराधिक कार्य

पूर्व-नियोजित योजना के अनुसरण में किया गया था और सामान्य इरादे का निष्कर्ष तब तक नहीं निकाला जाना चाहिए जब तक कि यह मामले की परिस्थितियों से आवश्यक निष्कर्ष न हो।”

48) उन्होंने चितरमल और अन्य बनाम् राजस्थान राज्य¹¹ और उसके पैरा 14 पर भरोसा किया, जो निम्नानुसार है:

"14. यह विनिश्चयों की एक श्रृंखला द्वारा अच्छी तरह से तय किया गया है कि धारा 34 और धारा 149 रचनात्मक अपराधिता अर्थात् दूसरों के कार्यों के लिए किसी व्यक्ति की अप्रत्यक्ष देयता के लिए दायित्व से संबंधित है। दोनों धाराएं ऐसे व्यक्तियों के संयोजन से संबंधित हैं जो किसी अपराध में भागीदार के रूप में दंडनीय हो जाते हैं। इस प्रकार उनकी एक निश्चित समानता है और कुछ हद तक अतिछादित हो सकती है। किंतु उस सामान्य आशय में सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य के बीच एक स्पष्ट अंतर किया जाता है जो कार्य को सम्मिलित रूप से दर्शाता है और आवश्यक रूप से एक पूर्व-व्यवस्थित योजना के अस्तित्व को अभिनिर्धारित करता है, जिसका अर्थ है मस्तिष्क की पूर्व बैठक, जबकि सामान्य उद्देश्य के लिए आवश्यक रूप से पूर्व-बैठक के सबूत की आवश्यकता नहीं होती है। यद्यपि दोनों धाराओं के बीच काफी अंतर है, वे भी कुछ हद तक अतिव्यापी हैं और यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर अवधारित किया जाने वाला प्रश्न है कि क्या धारा 149 के तहत आरोप धारा 34 के तहत आने वाले आधार को अतिव्यापी करता है। इस प्रकार, यदि पांच या अधिक संख्या वाले कई व्यक्ति कोई कार्य करते हैं और ऐसा करने का इरादा रखते हैं, तो धारा 34 और धारा 149 दोनों लागू हो सकते हैं। यदि सामान्य उद्देश्य में आवश्यक रूप से समान आशय अंतर्वलित नहीं है तो धारा 149 के लिए धारा 34 का अभियुक्त पर

11 (2003) 2 एससीसी 266

प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है और इसलिए अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। किंतु यदि इसमें एक समान आशय अंतर्वलित है तो धारा 149 के स्थान पर धारा 34 का प्रतिस्थापन एक औपचारिक मामला होना चाहिए। इस तरह का सहारा लिया जा सकता है या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है। धारा 149 की गैर-प्रयोज्यता, इसलिए, आईपीसी की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के तहत अपीलार्थियों को दोषी ठहराने में कोई प्रतिबंध नहीं है, यदि साक्ष्य निम्नलिखित के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए किसी अपराध के किए जाने का खुलासा करता है। उन सभी को (बरेंद्र कुमार घोष बनाम राजा देखें) सम्राट [एआईआर 1925 पीसी 1:26 क्री. एल. जे. 431], मन्नम वेंकटदारी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य [(1971) 3 एस. सी. सी. 254:1971 एस. सी. सी. (क्रिमि.)ए. आई. आर. 1971 एस. सी. 1467), नेथल पोथुराजू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य [(1992) 1 एस. सी. सी. 49:1992 एससीसी (क्रिमि) 20:एआईआर 1991 एससी 2214) और राम टहल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(1972) 1 एससीसी 136:1972 एससीसी (क्रिमि) 80:एयर 1972 एस सी 254]]”

49) उपर्युक्त निर्णयों में अधिकथित विधि के बारे में कोई विभेद नहीं हो सकता है जहां भारतीय दंड संहिता की धारा 34 और धारा 149 के बीच सूक्ष्म अंतर किया गया है जो क्रमशः 'सामान्य आशय' और 'सामान्य उद्देश्य' से संबंधित है। साथ ही, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा कि क्या आईपीसी की धारा 34 या धारा 149 या दोनों प्रावधान लागू होते हैं। यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि भा. दं. सं. की धारा 149 के लागू न होने का अभियुक्त व्यक्तियों को भा. दं. सं. की धारा 302 के अधीन, जो भा. दं. सं. की धारा 34 के साथ पठित है, दो-सिद्ध करने के लिए कोई वर्जन नहीं है, यदि साक्ष्य उन सभी के समान आशय को आगे बढ़ाने में अपराध किए जाने का खुलासा करता है। वर्तमान मामले के तथ्यों से, हम संतुष्ट हैं कि

नीचे की अदालतों ने सही निष्कर्ष निकाला है कि सिद्धदोषी व्यक्तियों द्वारा फिरौती के लिए अपराध करने का एवं समान इरादा था।

50) ए-14, के हैसियत से यह अतिरिक्त रूप से प्रस्तुत किया गया था कि पीडब्ल्यू-17 ने किसी विशेष घर की पहचान नहीं की थी। हालांकि, यह रिकॉर्ड पर आया है कि आरोपी श्याम बिहारी पासवान ने अपने इकबालिया बयान में कहा था कि पीड़ितों को ग्राम दिलहुआ में उनके घर में रखा गया था, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा इस कारण से मान्यता दी गई है कि इसकी पुष्टि पीडब्ल्यू-17 के साक्ष्य द्वारा की गई है जिसने ए-14 के घर की पहचान की थी। इसलिए, यह तर्क सही नहीं है कि किसी विशेष घर की पहचान नहीं की गई है।

51) परिणामस्वरूप, इन अपीलों को भी खारिज कर दिया जाता है।

2012 की आपराधिक अपील संख्या 708

52) यह अपील अंगद कोइरी (ए-9) द्वारा दायर की गई है। उसके खिलाफ आरोप है कि वह उस टीम का हिस्सा था जिसने पीड़ितों का अपहरण किया था। उसकी पहचान टीआईपी के साथ-साथ अदालत में भी की गई थी। इन पहलुओं को विद्वान अधिवक्ता द्वारा उचित रूप से स्वीकार किया गया था। तथापि, उसका एकमात्र तर्क यह था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 364 क के अधीन उसे सिद्ध करने का कोई कारण नहीं था और उसकी दोषसिद्धि भारतीय दंड संहिता की धारा 364 के अधीन होनी चाहिए थी।

53) एक बार जब हम यह पाते हैं कि तीन व्यक्तियों के अपहरण में ए-9 की भूमिका किसी भी संदेह से परे स्थापित हो जाती है और यह भी स्थापित हो जाता है कि अपहरण फिरौती के लिए था जिसकी वास्तव में मांग की गई थी और उपरोक्त कार्यों के पीछे एक आम इरादा था, ए-9 को भारतीय दंड संहिता की धारा 364 ए के तहत सही ठहराया गया है। परिणामस्वरूप, 2012 की आपराधिक अपील संख्या 708 को भी खारिज की जाती है।

2012 की आपराधिक अपील संख्या 707

54) यह अपील ए-1 कृष्ण बिहारी सिंह @कृष्णा सिंह द्वारा दायर की गई है। जहां तक ए-1 का संबंध है, वह उन लोगों में से एक है जिन्होंने पीडब्ल्यू-17,18 और 20 का अपहरण किया था। हमारा उद्देश्य उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय में उसके द्वारा की गई चर्चा को पुनः प्रस्तुत करके पूरा किया जाएगा, जैसा कि बहस के दौरान, इस अपीलार्थी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता कोई भी तर्क किसी भी विचार के योग्य नहीं बना सके:

“52. अपीलकर्ता भारतीय दंड संहिता की धारा 364 क/34,395 और 412 के अधीन दोषसिद्ध है और उसे मृत्युदंड दिया गया है। पी० डब्लू 17 में कहा गया है कि अपहर्ताओं द्वारा जिप्सी को रोकने के बाद बोलेरो चलाने वाला व्यक्ति राइफल लेकर बाहर निकला और उसके सहयोगियों ने उसे बाबू साहब के नाम से संबोधित किया। आरोपी, जिसे वर्मा जी कहा जाता था, ने 27 न्यूज़ पेपर में लिपटी हुई दो पैकेट पैसे निकालकर बोलेरो चलाने वाले व्यक्ति को दे दिए, जो रात 9 बजे वहां से चला गया। उसके चेहरे (आरोपी श्याम बिहारी पासवान) पर तील का निशान था। उसके घर पर छापा मारा गया था, परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था, और बोलेरो वाहन, पैसे और उसकी राइफल जब्त की गई थी। पीड़ितों को शाम 4 बजे अगवा कर लिया गया और वे रात 9 बजे तक बोलेरो में उनके साथ रहे। गवाह ने आगे कहा कि आरोपियों ने घटना के दौरान अपने चेहरे को ढका नहीं था। पी० डब्लू 17 ने अपने सहयोगियों द्वारा अपहरण के दौरान संदर्भित 'बाबू साहब' की अपनी पहचान से इस अपीलकर्ता की पहचान की। तब आरोपी ने अपना नाम कृष्ण बिहारी सिंह बताया था। यह पी. डब्ल्यू. 17 द्वारा की गई एक पूरी तरह से प्राकृतिक और विश्वसनीय पहचान थी, जब वह एक फोटोग्राफिक पुनरुत्थान द्वारा अपने मन में अपहरण नाटक को स्पष्ट रूप से पुनर्जीवित कर रहे थे।

यह कि अपीलार्थी को टी. आई. पी. पर नहीं रखा गया था, लेकिन अपहरण से रिहाई के 10 महीनों के बाद पहली बार कठघरे में पहचाना गया था, वर्तमान मामले के तथ्यों में कोई प्रासंगिकता नहीं है। इसी प्रकार, पी. डब्ल्यू. 18 या 20 द्वारा उसकी पहचान का अभाव भी अभियोजन पक्ष के मामले के लिए महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि यह गवाहों की संख्या नहीं है बल्कि एकमात्र गवाह की विश्वसनीयता का मुद्दा है, जिसमें परीक्षण निहित है। जहां पीड़ित ने अज्ञात अभियुक्त की केवल एक झलक देखी होगी और उसे याद रखने के लिए कोई विशेष कारण नहीं हो सकता है, वहां यह अधिक उपयुक्त है। ऐसे अभियुक्त की टी. आई. पी. को केवल इस सहायता के रूप में उचित माना गया है कि जांच 28 सही दिशा में आगे बढ़ रही थी। इस तरह की पहचान अपने आप में कोई ठोस सबूत नहीं है, बल्कि यह केवल पुष्टि करने वाला है। मामले के तथ्यों में, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, इस न्यायालय को कठघरे में अपीलार्थी की पहली पहचान में कोई कमजोरी नहीं मिली। अपीलकर्ता के घर से अपहरण में प्रयुक्त बोलेरो वाहन बरामद किया गया। यह उसके परिसर की सीमाओं से बरामद किया गया था या उसके घर के सामने सड़क पर खड़ा किया गया था और सड़क के दोनों तरफ मकान थे, यह शायद ही प्रासंगिक है और उसके स्वामित्व की कमी का बचाव नहीं करता है। पी. डब्ल्यू. 17 और 18 दोनों ने अपने साक्ष्य में क्रमशः न्यायालय में लाल रंग के मखमली सीट कवर और परीक्षण पहचान परेड द्वारा चांदी के रंग के बोलेरो की स्पष्ट पहचान की है। नकद के दो पैकेट अपीलकर्ता को उसके सहयोगियों द्वारा दिए गए समाचार पत्र में लपेटे हुए थे, जिसमें कुल एक लाख पचास हजार थे, जिस पर 'अंसारी नुआओ' लिखा हुआ था, वह पैसा दिया गया था। पीडब्लू 4 से पीडब्लू 17 को पीडब्लू 18 द्वारा काले बैग में रखा गया था। पी. डब्ल्यू. 17 में कहा गया है कि यह धन पी. डब्ल्यू. 18 को सौंपने से पहले समाचार पत्र

में लिपटा हुआ था, जिसने इसे काले बैग में रखा था। अपीलार्थी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ३१३ के तहत अपने बयानों में पहले कहा कि यह धन उसकी पत्नी के नाम पर क्रेडिट कार्ड से निकाला गया था, और बाद में कहा कि यह उसके चिमनी व्यवसाय से उसकी आय थी। बचाव में पेश की गई उसकी बैंक पासबुक में धन के स्रोत के लिए अपने प्रश्नगत न्यायोचित ठहराने के लिए उस अवधि के दौरान दावा की गई प्रकृति की निकासी नहीं दिखाई गई। अपीलार्थी का अस्थिर रुख स्वयं इस न्यायालय को संतुष्ट करता है कि वह सच नहीं बोल रहा था। पी. डब्ल्यू. 17 और 18 दोनों ने क्रमशः टी. आई. पी. और न्यायालय में उनके द्वारा वर्णित राइफल की विशेषताओं के आधार पर अपीलार्थी द्वारा अपने पास रखी गई राइफल को भी मान्यता दी। यह जब्ती अपीलार्थी के घर से प्रभावित हुई थी और उसके नाम पर एक लाइसेंसी हथियार साबित हुई। अंतिम लेकिन सबसे कम नहीं, बोलेरो उत्तर प्रदेश से चोरी किया गया वाहन निकला, जिस पर मूल रूप से एक दुपहिया वाहन को आवंटित किया गया फर्जी पंजीकरण नंबर था। ऐसी घटनाएं जो अपीलकर्ता की व्यवस्था के बारे में स्वयं बात करती हैं। इसलिए, यह न्यायालय, पूर्वोक्त चर्चा के प्रकाश में अभिनिर्धारित करता है कि अपीलार्थी की अपहरण और परिरोध में पहचान और अंतर्वेशन स्पष्ट रूप से साबित हो जाता है। जांच के दौरान पुलिस को दी गई जानकारी के आधार पर उपरोक्त वस्तुओं की बरामदगी, जिसे टी. आई. पी. में चिन्हित किया गया था, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत स्वीकार्य साक्ष्य था।”

55) परिणामस्वरूप, यह अपील खारिज की जाती है।

2013 की आपराधिक अपील संख्या 1858

56) हरबंस राम (ए-8) इस अपील में अपीलकर्ता है। उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 364 ए/34 के तहत दोषी ठहराया गया है और भारतीय दंड संहिता की धारा 412 के तहत आरोप से बरी कर दिया गया है। उनके अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि उनका नाम प्रथम आरोपपत्र में नहीं है। इसके अलावा, जहां तक ए-8 का संबंध है, आरोप केवल धारा 368 और 412 भ० द० स० के तहत विरचित किए गए थे। भारतीय दंड संहिता की धारा 412 और इसलिए धारा 364 ए/34 के तहत उसकी दोषसिद्धि कानूनी रूप से मान्य नहीं थी।

57) जहां तक अधिवक्ता का तर्क है कि आरोप पत्र में ए-8 का नाम नहीं है, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, जांच अधिकारी (पीडब्लू-19) ने विस्तार से बताया है कि जांच के दौरान, इन आरोपी व्यक्तियों के नाम सामने आते रहे हैं और तदनुसार जांच आगे बढ़ी है। यही कारण है कि दूसरा आरोप पत्र ए-8 सहित अन्य व्यक्तियों को शामिल करते हुए दायर किया गया। दिलचस्प बात यह है कि उच्च न्यायालय में ऐसा कोई तर्क नहीं दिया गया था।

58) जहां तक धारा 364 क के तहत आरोप के अभाव का संबंध है, यह इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उसे आईपीसी की धारा 368 के तहत विशेष रूप से आरोपित किया गया था, इस अपीलकर्ता के लिए चीजों को बेहतर नहीं बना सकता है, जो निम्नलिखित प्रभाव के लिए है:

“जो कोई यह जानते हुए कि किसी व्यक्ति का अपहरण कर लिया गया है या उसका अपहरण कर लिया गया है, ऐसे व्यक्ति को गलत तरीके से छिपाता है या परिरुद्ध करता है, उसे उसी प्रकार दंडित किया जाएगा जैसे उसने उसी आशय या ज्ञान के साथ या उसी प्रयोजन के लिए ऐसे व्यक्ति का अपहरण किया था या किया था जिस प्रयोजन के लिए वह ऐसे व्यक्ति को छिपाता है या परिरुद्ध करता है।”

59) यह उपबंध यह स्पष्ट करता है कि यह जानते हुए कि किसी अपहृत व्यक्ति का अपहरण कर लिया गया है, उसे गलत तरीके से छिपाने या परिरुद्ध करने वाला

व्यक्ति भी उसी तरह के परिणामों को भुगतता है, जिस तरह के परिणाम उसे भुगतने पड़ते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ३१३ के तहत आरोपों के बयान में, यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि उनके खिलाफ आरोप यह जानते हुए कि उनका अपहरण कर लिया गया था, अपहृत व्यक्तियों को बंधक बनाए रखने का था। इस प्रकार, ए-८ के खिलाफ अभियोजन द्वारा स्थापित विशिष्ट मामला यह था कि उसने पीड़ितों को इस जानकारी के साथ बंदी बना रखा था कि उनका अपहरण किया गया था। इस प्रकार, उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 368 के घटक को स्थापित किया गया है। एक बार जब यह साबित हो जाता है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 364 ए के परिणाम, जिसके लिए अन्य सह-अभियुक्त व्यक्ति दोषी पाए गए थे, आकर्षित होंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 368 में विहित अपराध को धारा 364 क के समकक्ष रखा गया है। सुमन सूद के मामले में, यह कानूनी सिद्धांत निम्नलिखित तरीके से निर्धारित किया गया है:

“60. फिरौती के लिए अपहरण किसी व्यक्ति को गैरकानूनी रूप से जब्त करने और फिर फिरौती वसूलने का प्रयास करते समय उस व्यक्ति को आमतौर पर एक गुप्त स्थान में सीमित करने का अपराध है। इस गंभीर अपराध को कभी-कभी मृत्युदंड का अपराध बना दिया जाता है। अपहर्ता के अलावा फिरौती वसूलने के लिए बीच-बचाव करने वाले व्यक्ति को आम तौर पर अपराध का दोषी माना जाता है।”

60) इसके अलावा, प्रत्यर्थी के विद्वत वकील ने उचित रूप से तर्क दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 464 में यह उपबंध किया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 464 के अधीन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 464 के अधीन कोई दंडादेश नहीं दिया जाएगा। सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय को इस आधार पर अविधिमान्य माना जाएगा कि कोई आरोप विरचित नहीं किया गया था या आरोप में कोई अनियमितता या आरोपों का मिलान नहीं किया गया था, जब तक कि न्यायालय इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता कि उसके द्वारा न्याय की विफलता हुई थी। वर्तमान मामले में, ए-८ के प्रति ऐसा कोई पूर्वाग्रह नहीं पैदा किया गया है जो उस पर लगाए गए आरोप के अवयवों को जानता था।

61) इस प्रकार, इस अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हुए, 2013 की आपराधिक अपील संख्या 1858 को भी खारिज कर दिया गया है।

2012 की आपराधिक अपील संख्या 703-704

62) किसी ने इन अपीलों पर बहस नहीं की। किसी भी मामले में, हमने इन अपीलों के संदर्भ में भी मामले की जांच की है और हमें इन अपीलार्थियों को दोषी ठहराने के नीचे के न्यायालयों के फैसले में कोई त्रुटियां नहीं मिली हैं। इसलिए हम इन अपीलों को भी खारिज करते हैं।

63) जुर्माने में, सभी अपीलों को खारिज कर दिया जाता है जिससे उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और दंड की पुष्टि होती है।

(ए. के. सीकरी, न्यायमूर्ति)

(आर. के. अग्रवाल, न्यायमूर्ति)

नई दिल्ली

6 अक्टूबर 2017

खण्डन (डिस्क्लेमर) :- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।